भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 9 जुलाई 2026 | 25 आषाढ़, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 75, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

एक करोड़ की हेरोइन समेत तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी, पंचकूला। पंचकूला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल (एएनसी) ने करीब 311 ग्राम हेरोइन के साथ एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश कुमार (33) निवासी गांव मटौर, थाना कलायत, जिला कैथल (हरियाणा) के रूप में हुई है। वह फिलहाल हिमाचल के बद्दी में किराये के मकान में रहकर पंचकूला और आसपास के इलाकों में हेरोइन की सप्लाई कर रहा था। सूचना के आधार पर एएनसी टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पारदर्शी पॉलिथीन में रखी 311 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर संजीव ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।

करंट लगने से एक ही परिवार के 4 लोग मरे

एजेंसी, मुंबई। महाराष्ट्र के सतारा जिले की फलटन तहसील के खामगांव में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा सामने आया। बिजली का करंट लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सतीश किसान शिंदे (45), उनकी पत्नी गंगू शिंदे (42) और उनके बच्चों सचिन व आरती के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, एक टूटा हुआ वायर मुख्य बिजली लाइन के संपर्क में आ गया था, जिससे उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। परिवार के एक सदस्य के संपर्क में आने के बाद बचाने की कोशिश में अन्य लोग भी चपेट में आ गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट से होगा दवाइयों का आयात

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाइयों के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश बिंदु घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की। मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले के बाद देश में दवाइयों के आयात के लिए अधिसूचित सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्गों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद किया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को सूची में शामिल करने से दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

कुलकर्णी और शिवराज की न्यायिक हिरासत 11 तक बढ़ी

एजेंसी, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपितों की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। इस मामले में अब तक 13 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

भारत और इंडोनेशिया मिलकर करेंगे 1000 साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार

प्रम्बानन में पीएम मोदी ने की शिव पूजा, बोले-भगवान शिव से जुड़ना मेरा सौभाग्य

एजेंसी, योग्याकार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल पुराने ऐतिहासिक प्रम्बानन हिंदू मंदिर में पूजा-अर्चना की और इसके संरक्षण व जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों देशों ने मंदिर के संरक्षण के लिए आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) का भी आदान-प्रदान किया। मंदिर परिसर में पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे हमेशा किसी न किसी रूप में भगवान शिव से जुड़ने का अवसर मिलता रहा है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद अब प्रम्बानन मंदिर के विकास से जुड़ना मेरा सौभाग्य है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत तथा सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर इस धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इस परियोजना में इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ तकनीकी सहयोग देगा।

अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति प्राबोवो ने प्रधानमंत्री मोदी को सुपर प्यूमा हेलिकॉप्टर से प्रम्बानन मंदिर परिसर का हवाई भ्रमण भी कराया। इसके बाद दोनों नेता सड़क मार्ग से मंदिर पहुंचे, जहां बच्चों ने उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में दोनों नेताओं ने रामायण पर आधारित सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति देखी और चल रहे संरक्षण कार्यों की जानकारी ली।

नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इसका मूल संस्कृत नाम शिवगृह है और मुख्य शिव मंदिर 47 मीटर ऊंचा है। वर्ष 2006 में आए भूकंप से इस परिसर को काफी नुकसान पहुंचा था। मोदी के इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन हुई यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। भारत इससे पहले वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बहरीन और बांग्लादेश सहित कई देशों में साझा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार में भी सहयोग करता रहा है।

दुनिया के हर कोने में दिखती है भारत की सांस्कृतिक विरासत: प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक अवश्य दिखाई देती है। प्रम्बानन मंदिर दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सबसे महत्वपूर्ण पहचान में से एक है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, मां दुर्गा और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित हैं तथा सदियों तक यहां गहरी आस्था के साथ पूजा-अर्चना होती रही है।

वीबी-जी-राम-जी योजना हिमाचल के हित में नहीं', केंद्र के समक्ष उठाएंगे मामला: सीएम सुक्खू

अनिल शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हिमाचल के समग्र विकास में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई भर्तियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बंद कर उसकी जगह 'वीबी-जी-राम-जी योजना' लागू करना हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करवाती थी, जबकि नई योजना में कुल खर्च का 10 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना होगा। इससे राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसलिए इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी। ऊना में बन रहे जिला पंचायत संसाधन केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव सी. पालरासु, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास योजनाओं की ऑनलाइन होगी निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को आजीविका मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 310 स्वयं सहायता समूहों को 65.56 लाख रुपये की ऋण सहायता प्रदान की जा चुकी है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए शिमला में 'हिमाचल हाट' का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पंडोह और कुल्लू में भी शोरूम स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि धर्मशाला में ऐसा शोरूम पहले से संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फूड वैन भी उपलब्ध करवाई गई हैं और भविष्य में ऐसी और वैन भी प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव को विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ने के निर्देश भी दिए, ताकि उनकी ऑनलाइन निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।

अमेरिकी हमले के बाद ईरान की चुनौती, हरगिज नहीं झुकेंगे

एजेंसी, मॉस्को

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालीबाफ़ ने बुधवार को कहा कि डराने-धमकाने और ब्लैकमेल करने से कोई नतीजा नहीं निकलता। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान हार नहीं मानेगा।

बुधवार रात, अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई ज़बरदस्त हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ये हमले होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाज़ों के खिलाफ़ ईरान की कार्रवाई के जवाब में किए गए थे। इन हमलों को लेकर गालीबाफ़ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'धौंस जमाने और जबरन वसूली का दौर खत्म हो गया है। इससे कुछ हासिल नहीं होता। हम झुकेंगे नहीं।'

उन्होंने अमेरिका पर उस समझौते (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) के कई बार गंभीर उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया, जिस पर दोनों पक्षों ने 18 जून को हस्ताक्षर किए थे। इन उल्लंघनों में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने के लिए ईरान की तय व्यवस्था का उल्लंघन, नए हमलों की लगातार धमकियां, तेल पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करना, दक्षिणी ईरान पर हमले और लेबनान के खिलाफ इजराइल की लगातार आक्रामकता शामिल है।

सीजफायर खत्म होने की खबर से बाजार में हड़कंप

भारी गिरावट: सेंसेक्स 1677 अंक टूटा, निफ्टी 23,882 पर हुआ बंद

एजेंसी, मुंबई

अमेरिका-ईरान सीजफायर खत्म होने की खबर के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स कारोबार के दौरान करीब 20 मिनट में 1000 अंक टूट गया और अंत में 1,677 अंक यानी 2.15 प्रतिशत गिरकर 76,504 के स्तर पर बंद हुआ।

सुबह सेंसेक्स 364 अंक की गिरावट के साथ 77,816 पर खुला था। दोपहर बाद बिकवाली बढ़ने से यह 76,259 के डे लो तक पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 516 अंक यानी 2.12 प्रतिशत गिरकर 23,882 पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट का असर ज्यादातर सेक्टरों पर देखने को मिला। निवेशकों में वैश्विक तनाव को लेकर चिंता बढ़ी, जिससे बिकवाली तेज हो गई। सीजफायर खत्म होने की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल करीब 6 प्रतिशत बढ़कर 75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता खत्म होने की बात कही, जिसके बाद बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई।

सोना 177 रुपए बढ़ा और चांदी पहुंची 2.27 लाख किलो

नई दिल्ली। सोने-चांदी के दाम में आज यानी 8 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 177 रुपए बढ़कर 1.44 लाख रुपए हो गया है। वहीं, 1 किलो चांदी का दाम 150 रुपए बढ़कर 2.27 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

सैनी से मिले आईकिया इंडिया के सीईओ चार हजार करोड़ के निवेश पर की चर्चा

एजेंसी, चंडीगढ़

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बुधवार को आईकिया इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक एंटोनी ने मुलाकात की। यह बैठक संत कबीर कुटीर में हुई। बैठक में हरियाणा में कंपनी के निवेश और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। आईकिया गुरुग्राम में करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। यह परियोजना लगभग 10 एकड़ में बनेगी। इसमें रिटेल स्टोर, ऑफिस और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 हजार रोजगार मिलने की संभावना है।

सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार निवेश करने वाली कंपनियों को बेहतर सुविधाएं व सहयोग दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आईकिया की भविष्य की योजनाओं में भी सरकार पूरा साथ देगी। बैठक के दौरान आईकिया के सीईओ ने मुख्यमंत्री को अगले साल गुरुग्राम में बनने वाले आईकिया स्टोर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हरियाणा को वैश्विक कंपनियों के लिए एक बेहतर निवेश केंद्र बनाने में मदद करेगी।

धामी बोले-मंदिर में चोरी माता-पिता की हत्या जैसे महापाप के समान, दोषियों को नहीं छोड़ेंगे

एजेंसी, हरिद्वार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी करना गौ हत्या और माता-पिता की हत्या जैसे महापाप के समान है और ऐसा अपराध किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं है।

हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित मोरारी बापू की रामकथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर में चोरी अत्यंत गंभीर और अक्षम्य अपराध है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति अपना कार्य शुरू कर चुकी है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने भी तत्काल जांच समिति गठित की थी। इसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से यह संकेत मिला है कि सरकार पूरे मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या दोषियों को बख्शने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, उसी के अनुरूप जिम्मेदार लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

मानसून को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मानसून की तैयारियों पर भी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए हैं। संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी रहेगा और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

शोपियां मुठभेड़ में लश्कर कमांडर जाकिर मारा गया

एजेंसी, शोपियां। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चनापोरा इलाके में चल रहे आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर गनी मारा गया है जबकि एक और आतंकवादी के छुपे होने की आशंका है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जाकिर पिछले पांच दिनों से अपने साथी के साथ मुठभेड़ में फंसा हुआ था। उन्होंने कहा, 'उसे मार गिराया गया है और आज हथियारों और गोला-बारूद के साथ एक गौशाला से उसका शव बरामद किया गया।

उन्होंने इस घटना को सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ स्थल के पास फिर से गोलीबारी की आवाज सुनी गई, जिससे एक और आतंकवादी की मौजूदगी का संकेत मिलता है। एक्स पर पोस्ट में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, 'आप भाग तो सकते हैं, लेकिन छुप नहीं सकते। एसओजी शोपियां ने सेना की आरआर और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर के एक आतंकवादी को मार गिराया।'

शिक्षा समाज की आधारशिला, इसके बिना विकास संभव नहीं: सीएम योगी

एजेंसी, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। साथ ही डीबीटी के माध्यम से प्रदेश भर के लगभग 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित की।

अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, बड़ा लालपुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ व हरित विद्यालयों के 12 प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कैशलेस इलाज के लिए साढ़े चार सौ करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे। इसका भुगतान प्रदेश सरकार करेगी।

उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के बदले में सरकार आपसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ एक चीज मांगती है कि बच्चों कि पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रदेश के स्कूल में स्वच्छता, पढ़ाई और बच्चों के विकास पर काम हो। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कर कहा कि वहां हर व्यक्ति हिंदी बोलता है। वहां के सांसद ने बताया कि जितने शिक्षक हमारे यहां हैं, सब उत्तर प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में भी भारी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश से हैं। शिक्षा समाज कि आधारशिला है। इसके बगैर कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह तथा माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

आसियान देशों के साथ भारत का कारोबार बढ़ा

2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार ने छुआ 128 अरब डॉलर का आंकड़ा

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत की आसियान देशों के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 128 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक आसियान देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत 6 से 10 जुलाई तक 13वीं आसियान-भारत व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) की संयुक्त समिति (जेसी) और उससे जुड़ी बैठकों की मेजबानी कर रहा है। आसियान भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 11 फीसदी हिस्सा है।

मंत्रालय के मुताबिक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में ये बैठकें भारत और आसियान के बीच सहयोग को गहरा करने, आपसी समझ को मजबूत करने और रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रही हैं। संयुक्त समिति की बैठक में उप-समितियों को उनके काम के क्षेत्रों में रणनीतिक मार्गदर्शन दिया गया और उनसे एआईटीआईजीए समीक्षा के तहत बाकी बचे अध्यायों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। बातचीत की गति बनाए रखने के लिए उप-समितियों को तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें सहमत समय-सीमा के अंदर ठोस नतीजे हासिल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि एआईटीआईजीए जॉइंट कमिटी के तहत आठ सब-कमिटी में से तीन की बैठकें अभी 13वीं संयुक्त समिति की बैठक के साथ-साथ हो रही हैं। इनमें कस्टम्स प्रक्रियाओं और व्यापार को आसान बनाने पर बनी सब-कमिटी (एससी-सीपीटीएफ), नेशनल ट्रीटमेंट और मार्केट एक्सेस पर बनी सब-कमिटी (एससी-एनटीएमए), और रूल्स ऑफ ओरिजिन पर बनी सब-कमिटी (एससी-आरओओ) शामिल हैं।

निर्णय गृह मंत्री अमित शाह ने एयरपोर्ट सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था में बड़े सुधार के दिए निर्देश

देश के सभी हवाई अड्डों पर लगेगी एटीआरएस

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने बुधवार को देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आव्रजन प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष तथा गृह एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमित शाह ने निर्देश दिया कि देश के सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्स-रे ट्रे रिटर्न प्रणाली (एटीआरएस) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे मानव संसाधन की आवश्यकता कम होगी व सुरक्षा जांच की प्रक्रिया अधिक तेज एवं प्रभावी बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नए हवाई अड्डों में इस प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त मानक निर्धारित किए जाएं। गृह मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डों पर प्रवेश द्वार, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच लेन और आप्रवासन काउंटर जैसी सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करते हुए व्यापक ढांचा तैयार किया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर यात्रियों की आवाजाही बाधित न हो। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टच-पॉइंट के लिए समन्वित योजना तैयार की गई है, जिससे यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।

शाह ने निर्माणाधीन 21 हवाई अड्डों तथा विकास के लिए चिन्हित 41 अन्य हवाई अड्डों को यात्री यातायात के आधार पर प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी 62 हवाई अड्डों पर विकास कार्य अगले दो वर्षों में पूरा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो तथा व्यावसायिक क्षेत्र निर्धारित मानकों के भीतर रहें।

उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यात्री और विमान यातायात के आधार पर सभी हवाई अड्डों पर एयरोब्रिज की संख्या तय करने के मानक तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, वर्तमान में 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध बैगेज ड्रॉप सुविधा को अधिक यात्री संख्या वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक विस्तारित करने को कहा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक्स-रे स्क्रीनिंग में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता के निर्धारित मानकों में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए व आवश्यक योग्यता वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को ही इस कार्य में लगाया जाए।

2027 तक हर राज्य की राजधानी में होगा एफआरआरओ

अमित शाह ने निर्देश दिया कि वर्ष 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) स्थापित कर दिए जाएं। उन्होंने अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर अधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) को लोकप्रिय बनाने के लिए एयरलाइंस के सहयोग से ऐसी व्यवस्था विकसित करने को कहा, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय टिकट बुक करते समय यात्रियों को व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

न्यूजीलैंड ट्रेड डील में बागवानों के हितों से न हो समझौता : विक्रमादित्य सिंह

विदेशी सेब आयात पर जताई चिंता, बोले- किसानों और बागवानों के हित सर्वोपरि

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज़ीलैंड दौरे के दौरान संभावित भारत-न्यूज़ीलैंड व्यापार समझौते को लेकर प्रदेश के बागवानों और किसानों के हितों की रक्षा की मांग उठाई है।

उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने चाहिए, लेकिन ऐसे किसी भी समझौते में हिमाचल के सेब उत्पादकों और किसानों के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि सेब और अन्य कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में और कमी किए जाने से प्रदेश के बागवानों को नुकसान हो सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में कहा कि अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते में सेब पर आयात शुल्क कम किए जाने के बाद अब न्यूज़ीलैंड के साथ संभावित समझौते को लेकर भी बागवानों में चिंता है।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना देश के लिए जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में हिमाचल के किसानों और बागवानों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सेब, स्टोन फ्रूट, डेयरी उत्पाद और दूसरे कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क लगातार कम होता है तो विदेशी उत्पाद कम कीमत पर भारतीय बाजार में पहुंचेंगे। इसका सीधा असर हिमाचल के बागवानों और किसानों की आय पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। जब भी प्रदेश के किसानों और बागवानों के हितों पर असर पड़ेगा, कांग्रेस सरकार उनकी आवाज उठाएगी और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

धर्म और आस्था पर किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की आस्था पर सवाल उठाने या किसी को हिंदू होने का प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर जाना और पूजा करना हर व्यक्ति का निजी विषय है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से डॉ. राजीव बिंदल का सम्मान करते हैं, फिर भी इस तरह के बयान प्रदेश के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल या नेता को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन कितना धार्मिक है। राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह स्वयं मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग कर चुके हैं और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि यदि राम मंदिर से जुड़े चंदे या भूमि खरीद-फरोख्त को लेकर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई है तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर मांग दोहराई कि इन आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

सेब सीजन की तैयारियों को लेकर अहम बैठक कल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सेब सीजन के दौरान बागवानों और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) रामपुर ने 10 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय रामपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगी। एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बैठक में पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत बोर्ड, परिवहन विभाग, एचआरटीसी, कृषि एवं उद्यान विभाग, एपीएमसी और एचपीएमसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा सेब परिवहन व लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रतिनिधियों व क्रेन सेवा संचालकों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में सेब सीजन के दौरान सड़क व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, बिजली-पेयजल आपूर्ति, परिवहन, विपणन, लोडिंग-अनलोडिंग व आपदा प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एसडीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

बिंदल बोले-जनता ने कांग्रेस को हर चुनाव में दिया जवाब अब प्रमाणपत्र बांटने की राजनीति छोड़ें विक्रमादित्य सिंह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें भाजपा या उनके नेताओं को किसी प्रकार का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 35 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा प्रमाणपत्र प्रदेश की जनता का विश्वास है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और स्वयं विक्रमादित्य सिंह को हाल ही में हुए पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जनता ने करारा जवाब दिया है। जनता ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी पराजय से उत्पन्न हताशा और निराशा में कांग्रेस नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रदेश की वास्तविक समस्याएं छिप नहीं सकतीं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता को केवल निराशा, आर्थिक संकट और अव्यवस्था दी है। सबसे बड़ा छल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ। चुनाव से पहले कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने और एक लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदेश का युवा आज भी सरकार से अपने वादों का हिसाब मांग रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार जवाब देने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

'राम मंदिर पर राजनीति कर रही कांग्रेस'

डॉ. बिंदल ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का इतिहास पूरे देश के सामने है। भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ, हजारों लोगों ने बलिदान दिए और लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया तथा तुष्टिकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी। आज वही कांग्रेस राम मंदिर और भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, जिसे प्रदेश और देश की जनता भली-भांति समझती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय अपनी विफलताओं का जवाब देना चाहिए। प्रदेश की जनता रोजगार, विकास, आर्थिक स्थिति और चुनावी वादों पर जवाब चाहती है। भाजपा जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार को उसके हर वादे और हर विफलता के लिए जनता के सामने जवाबदेह बनाएगी।

अंकों में नहीं की जा सकती वीरभद्र सिंह के योगदान की गिनती: विनय

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि वीरभद्र सिंह के कार्यों और प्रदेश के विकास में उनके योगदान की गिनती अंकों में नहीं की जा सकती। उनके असंख्य विकास कार्यों के कारण ही आज हिमाचल प्रदेश आधुनिक राज्य के रूप में पहचान बना पाया है।

विनय कुमार ने कहा कि वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों में बसने वाले नेता थे। उनका सरल स्वभाव, व्यक्तित्व और जनता के प्रति प्रेम उन्हें आम लोगों से जोड़ता था। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व कभी-कभार ही जन्म लेता है। उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में जहां प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार का योगदान अविस्मरणीय है, वहीं आधुनिक हिमाचल के शिल्पी के रूप में वीरभद्र सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में ठाकुर रामलाल, जय बिहारी लाल खाची, विद्या स्टोक्स सहित अनेक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश और देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि उन्होंने वीरभद्र सिंह के मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत की। उनके नेतृत्व, विकास की सोच और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशीलता से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वीरभद्र सिंह अपने आप में एक संस्थान थे, जो सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते थे। उन्होंने शिमला शहर के ऐतिहासिक स्वरूप और विरासत के संरक्षण पर हमेशा जोर दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधायक अनुराधा राणा, गोकुल बुटेल, अमित नंदा, विनोद जिंटा, उमा कौशल, जैनब चंदेल, छत्तर सिंह सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीबीएसई स्कूलों में 3468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी : रोहित

शिक्षा मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में डिजिटल शिक्षा, सीबीएसई स्कूलों और भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति की समीक्षा की

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें 19 श्रेणियों के 2,668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को भेजा जा चुका है, जबकि 800 अस्थायी अंग्रेजी और गणित अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है।

शिक्षा मंत्री बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ड्रॉइंग, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ललित कला और लोक प्रशासन सहित विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भर्ती जल्द पूरी की जाएगी।

डॉ. वाईएस परमार डिजिटल विद्यार्थी योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में 9,359 विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने शेष पात्र विद्यार्थियों को भी जल्द योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालय आईसीटी से जुड़ चुके हैं। 524 विद्यालयों में पुराने कंप्यूटरों के स्थान पर नए कंप्यूटर उपलब्ध करवाने की स्वीकृति मिल गई है, जबकि 777 विद्यालयों में बेहतर इंटरनेट और नेटवर्क सुविधा के लिए बीएसएनएल के साथ प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

सीबीएसई स्कूल पहल के तहत 158 विद्यालयों को पाठ्यक्रम की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 146 विद्यालयों को सीबीएसई संबद्धता मिल चुकी है। गुणवत्ता सुधार के लिए 400 अंग्रेजी और 400 गणित अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति की गई है।

बैठक में एसएमसी अध्यापक, कंप्यूटर अध्यापक, एलडीआर मामलों, शास्त्री पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि 191 चयनित शास्त्री अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 870 पीईटी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

मल्टी टास्क वर्कर भर्ती की समीक्षा में बताया गया कि स्वीकृत 8,000 पदों में से 6,703 पद भरे जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 503 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण पूरा किया गया है। शिक्षा मंत्री ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने की जानकारी दी और प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए।

आपदा प्रभावित विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त विद्यालयों के लिए 19 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं तथा कुल 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संदीपनी बोले-भाजपा को नसीहत देने से पहले आत्ममंथन करें विक्रमादित्य

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस परिवार पर अतीत में स्कूटरों पर सेब लादकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हों, वह आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता और राजनीति का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास और अपने परिवार के अतीत पर भी आत्ममंथन करना चाहिए।

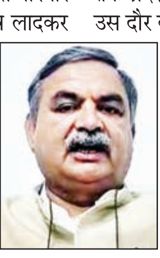

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भले ही विक्रमादित्य सिंह का परिवार स्वयं को राजघराने से जुड़ा हुआ बताता हो, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनकी अधिकांश पारिवारिक रिश्तेदारियां हिमाचल प्रदेश से बाहर हैं। ऐसे में प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों पर भाषण देने से पहले उन्हें अपने राजनीतिक और पारिवारिक आचरण पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मंत्री को वाकमुल्ला प्रकरण और वीरभद्र परिवार से जुड़े उन घटनाक्रमों का इतिहास भी भली-भांति याद होगा, जिनकी चर्चा वर्षों तक प्रदेश की राजनीति में होती रही। उस दौर के फार्महाउस और उससे जुड़े विवादों को भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इसलिए इतिहास को भूलकर दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास उचित नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस मंत्री अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी तथा असंतोष को भाजपा पर बयानबाजी के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के भीतर मतभेद हैं तो उनका समाधान पार्टी के अंदर होना चाहिए, भाजपा को अनावश्यक रूप से निशाना बनाना राजनीतिक हताशा का परिचायक है। संदीपनी ने कहा कि दूसरे राज्यों और वहां के लोगों पर टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस मंत्री को अपने पारिवारिक संबंधों और अपने ससुराल की ओर भी देख लेना चाहिए।

लाखों के गहने-नकदी उड़ाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

सीसीटीवी और तकनीकी जांच से सुलझी रोहड़ू में दिनदहाड़े घर से चोरी करने की वारदात

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला शिमला के रोहड़ू उपमण्डल में दिनदहाड़े हुई चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य वैज्ञानिक जांच के आधार पर किया गया। मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस के अनुसार 6 अप्रैल को रोहड़ू थाना में ग्राम खारला तहसील टिक्कर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि अज्ञात लोग दिन के समय उसके घर में घुस गए। आरोपियों ने गोदरेज अलमारी का ताला तोड़कर करीब 7.5 तोला सोने के आभूषण और 51 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस थाना रोहड़ू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(3), 305 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेकर संदिग्धों तक पहुंच बनाई गई।

पुलिस का कहना है कि इसी जांच के आधार पर चोरी की वारदात का खुलासा हुआ और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय राहुल निवासी जिला मंडी, 39 वर्षीय दीपक घई निवासी जिला मंडी और 30 वर्षीय मेहर चंद निवासी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने बुधवार को बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी राहुल और मेहर चंद पहले भी कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में चोरी के मामलों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस इन आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और इस वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार

शिमला। शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 8 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक वाहन को जांच के लिए रोका। वाहन में नितिश (28), पुत्र शिशु पाल, निवासी करासा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला और अंशवान मेहता (28), पुत्र विनोद कुमार, निवासी रोहल, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला सवार थे। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से करीब 8 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस थाना जुब्बल में केस दर्ज किया गया है।

2027 के चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस, पार्षदों को सौंपी जिम्मेदारियां

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी की संगठनात्मक बैठक में वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने की। इसमें नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल, कांग्रेस पार्षदों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बैठक में सभी वार्डों में कमेटियों के गठन को लेकर निर्णय लिया गया। वार्ड कमेटियों के गठन की जिम्मेदारी संबंधित पार्षदों को दी गई है और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। साथ ही जिला व प्रदेश कांग्रेस के आगामी आंदोलनों, रैलियों और कार्यक्रमों में पार्षदों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए अभी से फील्ड में सक्रिय होने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे।

हरित हिमाचल की दिशा में कदम, एचपीएमसी ने लागू की बोतल वापसी और रीसाइक्लिंग योजना

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए, हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने इस्तेमाल की गई और खाली कांच की बोतलों की रीसाइक्लिंग के लिए बायबैक योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को लागू किया है।

इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स) और वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) को एचपीएमसी की खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा, बल्कि योजना से जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

योजना के तहत, उपभोक्ता को अधिकृत रिटेलर के पास 200 मिलीलीटर की प्रत्येक खाली बोतल जमा करवाने पर एक रुपये और 600 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल पर दो रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, संग्रहण के अलग-अलग चरणों के अनुसार रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रति बोतल चार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

एचपीएमसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाली बोतलों को पहले रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एचपीएमसी के कार्यालयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें छंटाई और रीसाइक्लिंग के लिए जरोल स्थित एचपीएमसी के फल प्रसंस्करण संयंत्र भेजा जाएगा। बोतलों के संग्रह और परिवहन को सुचारु बनाने के लिए एक विशेष व्यवस्था भी बनाई गई है।

एचपीएमसी ने उपभोक्ताओं, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ एवं हरित बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की है। निगम का मानना है कि यह योजना कांच के कचरे को कम करने, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी एवं सतत व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के महत्व, नई शिक्षा व्यवस्था की जानकारी दी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी में बीए और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीप शिखा भारद्वाज ने की। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उच्च शिक्षा के महत्व, नई शिक्षा व्यवस्था तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी। प्राचार्या ने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और सद्भावना को जीवन में अपनाने का आह्वान किया तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया।

तैयारियां सीपी राधाकृष्णन के 10 जुलाई के प्रस्तावित आगमन को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

उपराष्ट्रपति के शिमला दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 10 जुलाई को प्रस्तावित शिमला प्रवास के दृष्टिगत जिला प्रशासन शिमला द्वारा आज सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापक तैयारियों संबंधी एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की।

बैठक में उपराष्ट्रपति के दौरे को सुचारु, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित प्रोटोकॉल एवं समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में हेलिकॉप्टर लैंडिंग स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सुरक्षित अवतरण एवं उड़ान, हेलीपैड की सुरक्षा, बैरिकेडिंग, स्वच्छता, संचार व्यवस्था तथा संबंधित एजेंसियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग को दौरे के दौरान समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, जीवन रक्षक औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अग्निशमन विभाग को हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अग्निशमन वाहनों, उपकरणों एवं प्रशिक्षित कर्मियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बैठक में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था, यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन, रूट प्लान, वीवीआईपी मूवमेंट, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों का निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मत, संचार व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, बिजली बैकअप, प्रोटोकॉल संबंधित व्यवस्थाएं तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए प्रत्येक व्यवस्था को समय से पूर्ण करने तथा किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला डॉ भुवन शर्मा, उपमंडल दण्डाधिकारी शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, उपमंडल दण्डाधिकारी शिमला शहरी ओशिन शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ यशपाल रांटा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

न्यूज ब्रीफ

बद्रीनाथ हाईवे पर बस और टैक्सी की भिड़ंत दो लोग चोटिल, अस्पताल में कराया भर्ती

भारतेंदु संवाददाता, चमोली। चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को एक सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए। ऊर्जा निगम कार्यालय को जाने वाले पैदल मार्ग के पास एक यात्री बस और टैक्सी वाहन की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों की सहायता की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब दोनों वाहन बद्रीनाथ हाईवे पर अपने-अपने मार्ग से गुजर रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि टैक्सी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

रुड़की के होटल में फौजी की मौत से फैली सनसनी

भारतेंदु संवाददाता, रुड़की। रुड़की के एक होटल में पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट निवासी 40 वर्षीय फौजी कमलदीप सिंह मृत पाए गए। वह पिछले दस दिनों से होटल में ठहरे हुए थे। कमरे का दरवाजा लंबे समय तक नहीं खुलने पर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उनका शव बिस्तर पर मिला। कमरे से कुछ दवाइयां और शराब भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

घने जंगल में रास्ता भटकीं पांच महिलाएं एसडीआरएफ ने 12 किमी पैदल चलकर किया रेस्क्यू

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पास घने जंगल में रास्ता भटक गईं पांच महिलाओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। सूचना मिलने के बाद मुख्य आरक्षी शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस व वन विभाग के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। दुर्गम जंगल में करीब 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद टीम ने सभी महिलाओं को खोज निकाला और सुरक्षित बाहर लाकर हर्रावाला पुलिस के सुपुर्द किया।

दून मेडिकल कॉलेज के मेस घोटाले का मास्टरमाइंड लेखाकार निलंबित

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों की मेस फीस से जुड़े घोटाले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में कथित मास्टरमाइंड माने जा रहे लेखाकार को जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है। छात्रों से मेस शुल्क निजी खातों में जमा कराने और डिमांड ड्राफ्ट वापस कराने की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। इससे पहले लेखा अनुभाग के चार कर्मचारियों के तबादले और वार्डनों में बदलाव की कार्रवाई भी की गई थी।

एसआईआर प्रपत्र में मिलीं पांच कमियां तो आएगा चुनाव आयोग का नोटिस, सॉफ्टवेयर करेगा छंटनी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। अगर आपने चुनाव आयोग का एसआईआर प्रपत्र भर दिया है तो भी आपको नोटिस आ सकता है। आयोग ऐसे करीब 18 लाख मतदाताओं का प्रपत्र में विसंगति के आधार पर नोटिस भेजने की तैयारी में है। इन नोटिस के हिसाब से मतदाताओं को अपने जवाब प्रमाण के साथ रखने होंगे। एसआईआर के दौरान मतदाताओं की मैपिंग में कुछ तकनीकी विसंगतियां सामने आई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इन त्रुटियों को स्पष्ट करते हुए इनके पांच प्रमुख कारणों की जानकारी दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सॉफ्टवेयर अभी सभी एसआईआर प्रपत्रों की पांच पैमानों पर छंटनी कर रहा है।

शहीदों के सम्मान से जुड़े मामलों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई: डीएम

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। जनपद में शहीदों के नाम पर स्मृतिद्वार एवं मोटर मार्गों के नामकरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी। कहा कि शहीदों के सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित प्रकरणों को 10 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। आज आयोजित बैठक में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी शहीद परिवारों के घर जाकर सम्मानपूर्वक दस्तावेज जमा करें।

जनसेवा शिविर में 128 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

भारतेंदु संवाददाता,पौड़ी गढ़वाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार संचालित सेवा, सुशासन एवं समर्पण-जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत बुधवार को विकासखंड दुगड्डा के जिला उद्योग केंद्र सभागार, कोटद्वार में जनसेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा।

शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतों और आवेदनों पर संबंधित विभागों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनेक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण-पत्र वितरण, स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी, रोजगार संबंधी पंजीकरण, औषधि वितरण तथा कृषि संबंधी सहायता उपलब्ध करायी गयी। अधिकारियों ने लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जनसेवा शिविर शासन और जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंच रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 19 जुलाई तक आयोजित होने वाले सभी शिविरों में अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न रखा जाए।

उत्तराखंड बनेगा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी : धामी

केदारखंड मानसखंड मंदिर माला मिशन से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर आश्रम में मोरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरिद्वार की पावन भूमि पर उन्हें अद्वितीय आध्यात्मिक सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है।

उन्होंने मोरारी बापू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उत्तराखंड आगमन देवभूमि के लिए ईश्वर की विशेष कृपा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरारी बापू केवल श्रीराम कथा के वाचक नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्शों, विचारों और जीवन-दर्शन के जीवंत संवाहक हैं। उन्होंने

प्रवचनों के माध्यम से विश्वभर में भारतीय संस्कृति, सनातन दर्शन और आध्यात्मिक चेतना का संदेश पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया युद्ध, हिंसा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत की सनातन संस्कृति का वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है और उत्तराखंड सरकार देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर तथा प्राचीन मंदिरों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

दो माह में 45 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में दो माह के भीतर 45 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा में 5500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य में बेहतर बुनियादी ढांचे, सुरक्षित यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था का प्रमाण है।

तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में हेड रेस टनल ब्रेकथ्रू सफल

एनटीपीसी की 520 मेगावाट परियोजना में अहम उपलब्धि, सुरंग का 80 फीसदी निर्माण पूरा

भारतेंदु संवाददाता, चमोली। चमोली जिले में निर्माणाधीन एनटीपीसी की 520 मेगावाट क्षमता वाली तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। परियोजना के तहत हेड रेस टनल (एचआरटी) का सफल ब्रेकथ्रू किया गया है। इस सफलता के साथ परियोजना के निर्माण कार्य को नई गति मिलने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार यह परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक था, जिसे निर्धारित योजना के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

ब्रेकथ्रू के दौरान फेस-02 और फेस-03 से बनाई जा रही सुरंगों को सटीक इंजीनियरिंग के माध्यम से आपस में जोड़ दिया गया। दोनों दिशाओं से चल रही खुदाई तय स्थान पर मिल गई, जो किसी भी लंबी सुरंग परियोजना में बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जाती है। इस कार्य के लिए फेस-02 से 1,748 मीटर तथा फेस-03 से

हेड रेस टनल ब्रेकथ्रू की सफलता का जश्न मनाते इंजीनियर और कर्मचारी।

981 मीटर तक सुरंग की खुदाई की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी लंबी दूरी तक दोनों ओर से खुदाई कर सुरंग को सटीक बिंदु पर जोड़ना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसके लिए आधुनिक तकनीक और उच्च स्तर की इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है।

एनटीपीसी के अनुसार परियोजना की कुल 12.1 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल में अब तक लगभग 9.7 किलोमीटर खुदाई पूरी हो चुकी है। यानी सुरंग निर्माण का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। यह प्रगति दर्शाती है कि परियोजना अपने अगले चरणों की ओर तेजी से बढ़ रही है। हेड रेस टनल जलविद्युत परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से नदी का पानी विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइनों तक पहुंचाया जाता है।

तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है। इसके पूरा होने पर राज्य और देश के बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है।

एनटीपीसी ने इस उपलब्धि को परियोजना से जुड़े इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया है। कंपनी का कहना है कि शेष निर्माण कार्य भी तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। हेड रेस टनल का सफल ब्रेकथ्रू परियोजना के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है और इससे इसके समय पर पूरा होने की उम्मीद और मजबूत हुई है।

उत्तराखंड की सामूहिक खेती योजना में बड़ा घोटाला, नेकोफ पर डेढ़ करोड़ हड़पने का आरोप

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सहकारी सामूहिक खेती योजना को उस समय बड़ा झटका लगा जब टिहरी जिले में संचालित पायलट परियोजना में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के कथित गबन का मामला सामने आया। किसानों की आय बढ़ाने, बंजर भूमि को दोबारा खेती योग्य बनाने और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अधिकारियों ने कार्यदायी संस्था नेकोफ के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है।

जानकारी के अनुसार राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत टिहरी जिले के मोगी गांव में सहकारी सामूहिक खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय सहकारी समिति ने

डेढ़ करोड़ के कथित गबन की जांच शुरू

पलायन कर चुके किसानों की लगभग 70 एकड़ बंजर भूमि को लीज पर लेकर सामूहिक खेती की पहल की थी। परियोजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना, किसानों को बेहतर आय उपलब्ध कराना तथा गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना था।

इसके लिए तकनीकी और व्यावहारिक सहायता देने की जिम्मेदारी नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेकोफ को सौंपी गई थी।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद शुक्ल ने बताया कि योजना का मूल उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और पर्वतीय इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

उत्तराखंड में तैयार होगा एआई रेडी एजुकेटर ईकोसिस्टम

यूपीईएस और उत्तराखंड सरकार बनाएंगे एआई आधारित शिक्षा तंत्र

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यूपीईएस और उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है। देहरादून स्थित यूपीईएस परिसर में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 45 प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोग, शिक्षण, शोध और नवाचार में इसकी भूमिका तथा एआई आधारित डिजिटल उपकरणों

के उपयोग की जानकारी दी गई। यूपीईएस के कुलपति डॉ. सुनील राय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करना और विद्यार्थियों तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है।

पहले चरण की सफलता के बाद 11 और 12 जुलाई 2026 को दूसरे चरण में 90 और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से उत्तराखंड के सरकारी शिक्षण संस्थानों में एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जुड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।

केदारनाथ ठहराव बिलों पर जांच पूरी: बीकेटीसी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में वित्तीय अनियमितता की परतें खुल रही हैं। बीते वर्ष चारधाम यात्रा में केदारनाथ मंदिर में अतिथियों को ठहराने के लिए बिलों के भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी है। आरटीआई से मामले का खुलासा होने के बाद बीकेटीसी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी चुकी है। इस पर कार्रवाई लंबित है।

वर्ष 2025 में दो मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। 30 अप्रैल से 15 मई तक केदारनाथ यात्रा पर आने वाले अतिथियों के लिए मंदिर समिति ने ठहरने की आवासीय व्यवस्था की। होटलों, लॉज, जीएमवीएन के विश्राम गृह में कमरों के बिलों के भुगतान के लिए वित्त अधिकारी व अध्यक्ष से अनुमति नहीं ली गई।

अधिकारियों ने अपने स्तर पर अनुमोदन देकर भुगतान के लिए छह लाख की अग्रिम राशि जारी कर दी। बीकेटीसी ने जांच में वित्तीय अनियमितता पाई है। जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी दी गई है। अब बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी में कार्रवाई के बाद केदारनाथ मंदिर में बिलों के भुगतान मामले में भी कार्रवाई की तैयारी है।

सतपुली, स्यूंसी झील निर्माण से पैदा होंगे आजीविका के नए अवसर: महाराज

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को सतपुली में ग्राम पंचायत कुल्हाड में बनने वाले कुल्हाड बैंड से किनसुर-भरवाड़ी-कैण्डुल-डलगांव-उमन-किनसुर मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। सतपुली झील और स्यूंसी झील के निर्माण से चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है।

सतपुली में क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज महाराज ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन,

प्रेम नगर आश्रम में मोरारी बापू से मिले धामी

जमरानी बांध और सौंग बांध जैसी बड़ी परियोजना पर तेज से काम चल रहा है। सतपुली में करीब 56 करोड़ की लागत से 750 मीटर लंबी झील बनाई जा रही है।

झील बनने से वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और यहां पैराग्लाइडिंग भी शुरू की जाएगी। जबकि बीरोंखाल विकासखंड में 123.41 करोड़ की लागत से बनने वाले स्यूंसी झील (बैराज) परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और जल संकट दूर होगा।

इस मौके पर भाजपा नेता सुयश रावत, जिलाध्यक्ष कमल किशोर, मंडल अध्यक्ष सरवेंद्र, जिला मंत्री बृजमोहन, बूथ अध्यक्ष दिगंबर, सुरेंद्र सिंह, गबर सिंह, अंकित, अनिता देवी, सुरेश कुमार आदि शामिल रहे।

55 दिन में होंगे शिक्षकों के तबादले

शिक्षा विभाग को मिला अतिरिक्त समय, शासन ने जारी किए नए आदेश

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षकों के अनुरोध आधारित तबादलों को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए 55 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। कार्मिक विभाग की सहमति के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने शिक्षा महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से उन शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो विशेष परिस्थितियों के आधार पर स्थानांतरण की मांग कर रहे थे।

तबादला अधिनियम 2017 के अनुसार प्रत्येक वर्ष शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए निर्धारित समय-सारणी तय की जाती है। इस वर्ष भी विभाग को तय समय के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से निर्धारित अवधि में आदेश जारी नहीं हो सके।

तबादला प्रक्रिया फिर होगी शुरू

शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तबादला अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत निर्धारित नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इनमें गंभीर रूप से बीमार अथवा दिव्यांग कर्मचारी, बीमार या दिव्यांग जीवनसाथी वाले कर्मचारी, मानसिक रूप से दिव्यांग अथवा विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता, दिव्यांग संतान वाले सेवारत दंपति शामिल हैं।

फैसला धामी सरकार का बड़ा फैसला, बिना मान्यता धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मदरसों के संचालन और मान्यता के लिए लागू किए गए कड़े प्रावधान

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से मदरसों के संचालन और मान्यता संबंधी नियमों को और अधिक सख्त बनाते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश प्रभावी हो गया है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो सके।

संशोधित अध्यादेश के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले कानून में यह व्यवस्था थी कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम को उत्तराखंड बोर्ड से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इसी प्रकार कानून की एक अन्य उपधारा में भी बोर्ड की स्वीकृति से संबंधित व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे प्राधिकरण को पाठ्यक्रम तैयार करने और शैक्षणिक निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अधिनियम की धारा-16 में किया गया है। अब यदि कोई मदरसा या अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बिना

गड़बड़ी मिलने पर लगेगा जुर्माना और होगी एफआईआर

मदरसों पर बढ़ी निगरानी और जवाबदेही

संशोधित कानून में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब केवल वही संस्थान मान्यता प्राप्त कर सकेंगे जो संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित हों। संस्थान का संचालन विधिवत पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या कंपनी के माध्यम से होना चाहिए तथा भूमि भी उसी संस्था के नाम दर्ज होनी चाहिए।

मान्यता के धार्मिक शिक्षा संचालित करता है अथवा मान्यता संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित संस्थान को बंद किया जा सकेगा, उसके संचालकों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

केजरीवाल का मंदिर प्रेम केवल चुनावी दिखावा : ढिल्लों

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले – आस्था नहीं, चुनावी मजबूरी में मंदिरों की याद; पंजाब की जनता राजनीतिक पाखंड का देगी जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले और उसकी जगह अस्पताल बनाने की बात करने वाले नेता के मुंह से आज मंदिरों और सनातन धर्म की बातें शोभा नहीं देतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल का मंदिरों और हिंदू धर्म का बार-बार उल्लेख करना केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा है और यह उनके 'चुनावी हिंदुत्व' का प्रदर्शन मात्र है।

ढिल्लों ने कहा कि केजरीवाल का पूरा राजनीतिक रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हमेशा सनातन धर्म और धार्मिक आस्थाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ और वोट हासिल करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब राजनीतिक दिखावे और वास्तविक आस्था के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ चुकी है। इसलिए केवल चुनावों के समय धार्मिक स्थलों का दौरा करने या धार्मिक विषयों पर बयान देने से लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक और पवित्र अवसर आया था, तब पूरा देश उत्सव और श्रद्धा में डूबा हुआ था। उस समय देश के विभिन्न वर्गों के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंचे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समारोह से दूरी बनाए रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर केवल राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया, जबकि उन्हें सीधे अयोध्या जाकर इस राष्ट्रीय आस्था के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था।

ढिल्लों ने कहा कि पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल द्वारा मंदिरों और हिंदू समाज का बार-बार उल्लेख करना इस बात का संकेत है कि उन्हें अब चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले मंदिरों और धार्मिक मुद्दों पर अलग रुख अपनाते रहे, वे अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने केजरीवाल के धार्मिक ज्ञान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनवरी 2025 में रावण को लेकर दिया गया उनका विवादित और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान आज भी लोगों को याद है। ढिल्लों ने कहा कि जिस व्यक्ति को रामायण की मूलभूत जानकारी तक स्पष्ट नहीं है, वह आज पंजाब की जनता को धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि धर्म केवल चुनावी भाषणों का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है, जिसका सम्मान सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगभग एक दशक तक सत्ता में रहते हुए हिंदू धार्मिक स्थलों, मंदिरों या धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण और विकास के लिए कौन-से उल्लेखनीय कार्य किए।

झामपुर में चारदीवारी गिराने पर किसान ने जेई पर लगाए आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

मोहाली के गांव झामपुर, बड़माजरा, जुझारनगर, बहलोलपुर, ठस्का और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और कब्जों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। गांव झामपुर के किसान गुरनाम सिंह ने गमाडा के एक जूनियर इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य प्रशासक को शिकायत भेजी है। किसान ने आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि की चारदीवारी को बनाए रखने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई और पैसे देने से इनकार करने पर कार्रवाई करते हुए दीवार गिरा दी गई।

गुरनाम सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गमाडा के जूनियर इंजीनियर एचएस खेड़ा ने उनकी करीब 10 मरले कृषि भूमि की चारदीवारी को लेकर ढाई लाख रुपये की मांग की थी। किसान का कहना है कि यह जमीन कृषि उपयोग के लिए है, जहां वह घरेलू जरूरतों के लिए सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्वत देने से मना करने के बाद 22 जून 2026 को जेई अन्य अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और उनकी चारदीवारी को गिरा दिया। किसान ने दावा किया कि पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, जिसे उन्होंने शिकायत के साथ साक्ष्य के रूप में अधिकारियों को भेजा है। शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी को धमकाया गया और जातिसूचक टिप्पणियां भी की गईं। किसान ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

न्यूज ब्रीफ

ज्यादा बिजली उपयोग पर लगेगा दोगुना शुल्क

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। घर या दुकान में बिजली उपकरणों की संख्या बढ़ाने के बावजूद यदि उपभोक्ताओं ने अपना स्वीकृत बिजली लोड नहीं बढ़वाया है, तो अब उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने उपभोक्ताओं को लोड तुरंत अपडेट कराने की सलाह दी है। कंपनी के अनुसार, स्वीकृत सीमा से अधिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं से दोगुना बिल वसूला जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि एसी, गीजर, इलेक्ट्रिक

वाहन चार्जर और अन्य अधिक बिजली खपत वाले उपकरणों के बढ़ने से बिजली नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सीपीडीएल ने कहा कि निर्धारित लोड से अधिक उपयोग न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि इससे बिजली व्यवस्था और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने कनेक्शन का लोड बढ़वाएं, ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके।

संजीव अरोड़ा मामले में अदालत ने बढ़ाए दो सप्ताह

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। संजीव अरोड़ा ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की है। अब मामले में अगली सुनवाई के दौरान ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद अदालत याचिका पर आगे सुनवाई करेगी।

बारिश में डूबे सेक्टर-7 के वीवीआईपी बंगले

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। मानसून की पहली तेज बारिश ने चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर-7 स्थित सरकारी बंगलों की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर-7 के 16 सरकारी आवासों में बरसाती पानी घुस गया। प्रभावित बंगलों में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास शामिल हैं। सबसे ज्यादा असर बंगला नंबर-79 पर पड़ा, जहां हरियाणा सरकार के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर रहते हैं। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के आवासों के पीछे व परिसर में पानी भरने से नुकसान हुआ। यह क्षेत्र पंजाब राजभवन के सामने स्थित है और शहर के प्रमुख वीवीआईपी इलाकों में गिना जाता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आसपास की रोड गलियां और स्टॉर्म वॉटर लाइनें चोक होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी। अधिकारियों के अनुसार, पाइपलाइनों में जमा गाद के कारण जल निकासी क्षमता प्रभावित हुई। जलभराव के बाद नगर निगम ने सफाई अभियान चलाया, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। इसके बाद प्रभावित बंगलों के पीछे नई स्टॉर्म वॉटर लाइन डालने का काम शुरू किया गया। नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने भी माना कि रोड गलियां बंद होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी।

सेक्टर-53 हाउसिंग योजना फिर होगी बंद सीएचबी बोर्ड बैठक में लेगा अंतिम फैसला

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

करीब एक दशक से लंबित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की सेक्टर-53 सामान्य आवास योजना को फिर बंद करने की तैयारी है। बुधवार को होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में योजना को वापस लेने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

यूटी प्रशासक की मंजूरी के बाद योजना को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत 9 एकड़ भूमि पर 372 फ्लैट बनाए जाने थे, जिसमें एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान शामिल थे। हालांकि, आर्थिक व्यवहार्यता और भूमि उपयोग को लेकर विचार के बाद अब इसे बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। मार्च 2025 में हुए डिमांड सर्वे में योजना को अच्छा रिस्पांस मिला था। 372 फ्लैटों के लिए 7,468 आवेदन आए थे। इससे शहर में सीएचबी आवासों की मांग का पता चला। इसके अलावा बैठक में सेक्टर-51ए के फ्लैटों की लॉक-इन अवधि घटाने पर भी चर्चा होगी।

योजना बंद करने पर होगा फैसला

सीएचबी की यह योजना पहले भी कई बार विवादों और बदलावों के कारण प्रभावित हो चुकी है। वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना को फ्लैटों की अधिक कीमतों के चलते वापस लेना पड़ा था। उस समय प्रस्तावित 492 फ्लैटों के लिए अपेक्षा के अनुसार आवेदन नहीं मिले थे। इसके बाद योजना को नए सिरे से तैयार करने की कवायद शुरू की गई थी। बोर्ड बैठक में अब अधिकारियों की ओर से योजना को बंद करने के कारणों और भविष्य में सेक्टर-53 की जमीन के उपयोग को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रशासन की ओर से पहले ही जमीन के बेहतर इस्तेमाल और आर्थिक रूप से व्यवहारिक विकल्प तलाशने के निर्देश दिए गए थे।

पहली बारिश से पहले मोहाली की जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मानसून की शुरुआत के साथ ही मोहाली में जलभराव की पुरानी समस्या एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की सफाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने और जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के दावे किए हैं। हालांकि, शहर के लोगों का कहना है कि वर्षों से किए जा रहे इन दावों के बावजूद पहली तेज बारिश के साथ ही अधिकांश संवेदनशील इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

शहर के फेज-4, फेज-5, फेज-11, सेक्टर-70 और सेक्टर-71 सहित कई क्षेत्र हर वर्ष बारिश के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इन इलाकों में सड़कों पर कई फुट तक पानी भर जाता है, जिससे सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगती हैं। कई स्थानों पर जल निकासी बाधित होने के कारण बारिश का पानी घरों

और दुकानों तक पहुंच जाता है। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ दैनिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी होती है। जलभराव के कारण यातायात प्रभावित होता है, वाहन खराब हो जाते हैं और कई बार लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। वहीं, गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

नगर निगम के नवनियुक्त मेयर सरबजीत सिंह समाना के सामने भी जलभराव की समस्या सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। निगम का कहना है कि इस बार स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क की सफाई, नालों की डिसिल्टिंग, जल निकासी लाइनों की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है ताकि भारी बारिश के दौरान पानी जल्द निकाला जा सके।

दो शादियां छिपाकर युवती से ठगी और दुष्कर्म करने पर दोषी को उम्रकैद की सजा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

दो शादियां छिपाकर खुद को अमेरिकी नागरिक बताने, तीसरी शादी करने, दुष्कर्म करने और युवती के परिवार से 75 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में जिला अदालत ने जालंधर निवासी जगजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। करीब चार वर्ष पहले दर्ज इस चर्चित मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जगजीत सिंह को दोषी ठहराया, जबकि उसके साथ आरोपित बनाए गए चार कथित रिश्तेदारों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जगजीत सिंह पहले से दो शादियां कर चुका था और उसकी पहली पत्नी से एक बेटी भी है। इसके बावजूद उसने अपनी वैवाहिक स्थिति को पूरी तरह छिपाकर एक वैवाहिक वेबसाइट पर नया प्रोफाइल बनाया। इस प्रोफाइल में

उसने स्वयं को अविवाहित, संपन्न और अमेरिका का नागरिक बताया। उसने दावा किया कि उसके पास अमेरिका और पंजाब में करोड़ों रुपये की संपत्ति है तथा वह एक सफल परिवहन कंपनी का संचालन करता है।

इसी दौरान चंडीगढ़ की एक युवती से उसकी बातचीत शुरू हुई। कुछ ही समय में उसने युवती और उसके परिवार का विश्वास जीत लिया। परिवार के सामने उसने खुद को बेहद प्रभावशाली और संपन्न व्यक्ति के रूप में पेश किया। उसने अपने माता-पिता की मृत्यु को लेकर भी झूठी कहानी गढ़ी और बताया कि उसके पिता की कैंसर से तथा मां की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है।

मई 2022 में दोनों परिवारों की मुलाकात कराई गई और 25 मई को रोका समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जगजीत के साथ मामा-मामी और अन्य रिश्तेदार बनकर कुछ लोग भी पहुंचे, जिससे युवती के परिवार को उस पर पूरा भरोसा हो गया। बाद में जांच में सामने आया कि ये सभी लोग उसके असली रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि केवल विश्वास दिलाने के लिए बुलाए गए थे।

इसके बाद जून 2022 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जगजीत का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही विभिन्न बहानों से युवती के परिवार पर आर्थिक दबाव बनाकर उनसे 75 लाख रुपये भी ले लिए। शादी, सगाई, अंगूठी समारोह और अन्य कार्यक्रमों का पूरा खर्च भी पीड़ित परिवार ने ही उठाया। कुछ समय बाद युवती को पति की गतिविधियों पर संदेह होने लगा। एक दिन उसने घर की अलमारी में रखा एक बैग खोला, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि जगजीत सिंह पहले से दो शादियां कर चुका है ।

बल्लोपुर भूमि लीज मामले में गुरप्रीत को मिली जमानत

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

ग्राम पंचायत बल्लोपुर की शामलात भूमि लीज मामले में यूनिवर्सल एजुकेशनल सोसाइटी के प्रधान गुरप्रीत सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दाखिल हलफनामे के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता कि पंचायत की जमीन पर कोई ऐसा अवैध बोझ बनाया गया हो, जिससे जमीन के स्वामित्व अधिकार प्रभावित हों। अदालत ने माना कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

◆ अदालत ने बैंक हलफनामे के आधार पर हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं मानी

मामले में आरोप है कि ग्राम पंचायत बल्लोपुर की करीब 68 बीघा 14 बिस्वा शामलात भूमि 33 वर्षों के लिए सोसायटी को लीज पर दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लीज की मूल शर्तों में बाद में बदलाव कर जमीन पर ऋण लेने का प्रावधान जोड़ा गया, जिससे सोसायटी को लाभ पहुंचाया गया।

वहीं, पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सुशील कुमार अरोड़ा ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर बताया कि पंचायत की जमीन का स्वामित्व कभी भी सोसायटी या बैंक के पास नहीं रहा। बैंक ने केवल लीज अधिकारों को ऋण सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया था। ऋण के लिए आरोपी की निजी संपत्तियां भी गिरवी रखी गई थीं।

फेज-6 सिविल अस्पताल में थायराइड जांच दो सप्ताह से ठप, मरीज परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल में पिछले करीब दो सप्ताह से थायराइड फंक्शन टेस्ट (टीएफटी) की किट खत्म होने के कारण जांच पूरी तरह बंद पड़ी है। इसका सीधा असर रोजाना अस्पताल आने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को या तो इंतजार करना पड़ रहा है या फिर निजी प्रयोगशालाओं का रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से जांच बंद होने संबंधी कोई सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किए जाने के कारण मरीज पहले अस्पताल पहुंचते हैं और लैब में जाकर ही उन्हें किट उपलब्ध न होने की जानकारी मिलती है।

फेज-6 सिविल अस्पताल जिले के प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल है, जहां प्रतिदिन करीब 1500 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में विभिन्न प्रकार की जांचें सरकारी प्रयोगशाला और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत

संचालित प्रयोगशाला में की जाती हैं। लेकिन सरकारी लैब में टीएफटी की किट समाप्त होने से पिछले दो सप्ताह से यह महत्वपूर्ण जांच नहीं हो पा रही है।

थायराइड की समस्या से पीड़ित मरीजों के लिए नियमित अंतराल पर जांच कराना बेहद जरूरी माना जाता है। चिकित्सक दवा की मात्रा तय करने और बीमारी की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर टीएफटी कराने की सलाह देते हैं। ऐसे में जांच बंद होने से पुराने मरीजों के साथ-साथ नए मरीजों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को इलाज आगे बढ़ाने के लिए रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी चिकित्सा प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

अस्पताल में सरकारी लैब में टीएफटी जांच का निर्धारित शुल्क 225 रुपये है। वहीं, अस्पताल परिसर में ही पीपीपी मॉडल पर संचालित लैब में यही जांच 125 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जो सरकारी दर से 100 रुपये कम है। इसके बावजूद कई मरीज सरकारी लैब में जांच की सुविधा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ।

डीए बकाया मामले में आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

सरकार को बकाया भुगतान की योजना अदालत में बतानी होगी, कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें अब अगली सुनवाई पर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाये के भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस सुनवाई पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अदालत सरकार द्वारा बकाया भुगतान के लिए तैयार किए गए रोडमैप की समीक्षा करेगी।

इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 8 अप्रैल को पंजाब सरकार को 30 जून तक कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया डीए और डीआर जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि पंजाब सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन सरकार को सीलबंद

लिफाफे में भुगतान की विस्तृत योजना अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था।

अब अगली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होगा कि सरकार बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करेगी या किस्तों में देने का प्रस्ताव रखेगी। साथ ही यह भी सामने आएगा कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देकर अतिरिक्त समय की मांग करती है या नहीं।

पिछली सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपिंदर सिंह पटवालिया ने अदालत को बताया था कि डीए और डीआर के भुगतान के मामले में पंजाब सरकार केंद्र सरकार की नीति का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि उन्हें केंद्र सरकार की तर्ज पर समयबद्ध तरीके से डीए और डीआर का बकाया भुगतान किया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पंजाब सरकार का पक्ष है कि राज्य की वित्तीय स्थिति और लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब 9 जुलाई की सुनवाई में अदालत सरकार के भुगतान संबंधी प्रस्ताव और कानूनी पक्ष पर विस्तार से विचार करेगी।

डीए भुगतान पर समाधान की आस

इस मामले में कर्मचारियों और पेंशनरों का कहना है कि डीए और डीआर की लंबित राशि उनके अधिकारों से जुड़ी हुई है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें महंगाई के दौर में आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द बकाया राशि जारी करे, ताकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत मिल सके। वहीं, पंजाब सरकार की ओर से अदालत में वित्तीय स्थिति का हवाला दिया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य पर पहले से ही कई आर्थिक जिम्मेदारियां हैं और किसी भी भुगतान से पहले सभी पहलुओं का आकलन जरूरी है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भुगतान को लेकर व्यावहारिक योजना तैयार की जा रही है, जिसे अदालत के सामने रखा जाएगा। हाईकोर्ट के रुख के बाद अब सरकार पर बकाया भुगतान को लेकर स्पष्ट स्थिति रखने का दबाव बढ़ गया है।

बकाया राशि नहीं चुकाने वाले कॉलोनाइजरों पर होगी कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, बठिंडा

जालंधर। नगर निगम की करोड़ों रुपये की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले शहर के करीब 100 कॉलोनाइजरों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ बीएनएस और पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा एक्ट) के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन मामलों में एफआईआर दर्ज हो सकती है।

नगर निगम के मेयर वनीत धीर ने बताया कि निगम की ओर से कई बार डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए थे और सार्वजनिक रूप से भी बकाया राशि जमा कराने की अपील की गई थी, लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद अब ऐसे कॉलोनाइजरों की सूची पुलिस विभाग को भेज दी गई है, ताकि नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सके। मेयर ने बताया कि निगम ने केवल पुलिस कार्रवाई तक ही मामला सीमित नहीं रखा है। डिप्टी कमिश्नर को भी पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि जिन कॉलोनियों में संबंधित कॉलोनाइजरों के खाली प्लॉट मौजूद हैं, उनकी रजिस्ट्री और अन्य संपत्ति संबंधी लेन-देन पर रोक लगाई जाए। इससे बकाया राशि की वसूली में मदद मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2013 और 2018 में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नीतियां लागू की थीं। उस दौरान कई कॉलोनाइजरों ने अपनी कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए आवेदन किए थे, लेकिन निर्धारित विकास शुल्क और अन्य देय राशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते नगर निगम का करोड़ों रुपये का राजस्व लंबे समय से अटका हुआ है। नगर निगम ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी राजस्व की वसूली के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई की सूची में लद्देवाली, मकसूदां, चौहंका, दकोहा, ढिल्लवां, किंगरा, सुच्ची पिंड, मिट्ठापुर, बड़िंग, कालिया कॉलोनी समेत शहर के कई क्षेत्रों की कॉलोनियां शामिल हैं। निगम की इस कार्रवाई से बकाया राशि नहीं चुकाने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि शहर में अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर रोक लगाना भी है। निगम अब सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही अन्य डिफॉल्टरों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों के अनुसार विकसित कॉलोनियों में ही संपत्ति खरीदें।

निगम की नई रणनीति

नगर निगम ने बकाया वसूली अभियान को तेज करने के लिए संबंधित विभागों के साथ तालमेल बढ़ा दिया है। अधिकारियों की टीम अब कॉलोनियों की संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि डिफॉल्टरों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा ने सरकार को घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार हत्या, लूटपाट, फिरौती, गोलीबारी और हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण आम नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है।

◆पंजाब सुरक्षा पर भाजपा हमला

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का कोई भी नागरिक आज खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है और प्रदेश को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि राज्य में आए दिन हत्या, फिरौती, गोलीबारी और लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अखबारों के पन्ने रोजाना आपराधिक घटनाओं की खबरों से भरे रहते हैं। उनका आरोप है कि पंजाब में अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया है, जिसके चलते आम लोगों, व्यापारियों और कारोबारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि व्यापारियों को खुलेआम फिरौती के फोन आ रहे हैं और कई लोग डर के कारण पंजाब में कारोबार करने से भी हिचकिचाने लगे हैं। ढिल्लों ने कहा कि यदि व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो राज्य का आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बदलाव के नाम पर किए गए वादों का जवाब मांग रही है।

पीएम दौरे को लेकर रेलवे की तैयारियां तेज

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

रवनीत ने परखी स्टेशन की तैयारियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया।

जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य करीब 98.89 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि रेलवे की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में रेलवे के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व और प्रशासन की टीमें पंजाब दौरे को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिन्हें समय रहते दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे देशभर में पुराने स्टेशनों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 100 साल से अधिक पुराने करीब 1500 रेलवे स्टेशनों के विकास का कार्य चल रहा है और जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी इसी योजना का हिस्सा है।

रवनीत बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर दौरे के दौरान कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम की तारीख में बदलाव संभव है और अंतिम तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि 17 तारीख तक तैयार होने वाले कई रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन, रेलवे और भाजपा संगठन की ओर से तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं, स्थानीय लोगों में भी इस दौरे को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

कांग्रेस नहीं बदलेगी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने किया साफ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ

पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना कोई आसान फैसला नहीं है और यह कोई 'गुड्डे-गुड़िया का खेल' नहीं है।

भूपेश बघेल ने बताया कि पंजाब कांग्रेस के 23 जिला अध्यक्ष पहले ही राजा वड़िंग के नेतृत्व पर अपनी सहमति दे चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने राजा वड़िंग के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

हालांकि, पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की स्थिति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के गुट से जुड़े कई नेताओं ने भूपेश बघेल की ओर से बुलाई गई बैठकों से दूरी बनाए रखी है। जानकारी के अनुसार, सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके समर्थक कई विधायक बैठकों में शामिल नहीं हुए। भूपेश बघेल ने पार्टी नेताओं को अनुशासन में रहने की सलाह देते हुए कहा कि कोई भी नेता अपनी 'लक्ष्मण रेखा' पार न करे। उन्होंने साफ किया कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लुधियाना में राशन वितरण अभियान हुआ तेज

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले के लाखों लाभार्थी परिवारों को मुफ्त गेहूं वितरण का कार्य तेजी से जारी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, लुधियाना जिले में कुल 4,54,137 राशन कार्ड धारक परिवारों में से 4,24,132 परिवारों को उनके हिस्से का गेहूं उपलब्ध करवा दिया गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कंट्रोलर लखबीर सिंह संधू और कंट्रोलर सरताज सिंह चीमा की अगुवाई में गठित विभिन्न टीमों द्वारा राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जिले के साढ़े चार लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए कुल 25,159 मीट्रिक टन गेहूं का कोटा जारी किया गया है। इस अनाज को जिले के 1,602 राशन डिपुओं के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।

योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं के हिसाब से तीन महीनों का कुल 15 किलोग्राम गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। यह वितरण 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि के लिए जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक गेहूं वितरण का 93.39 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष परिवारों को भी जल्द गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय टीमें लगातार काम कर रही हैं।

इसके अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से पात्र परिवारों को राशन किटें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि विभाग को अब तक 2,80,000 राशन किटें प्राप्त हो चुकी हैं। इन राशन किटों में दाल, नमक, चीनी, हल्दी पाउडर और सरसों का तेल शामिल है।

अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत 2,51,000 परिवारों को राशन किटें वितरित की जा चुकी हैं। विभाग द्वारा जिले में राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में लुधियाना पूर्वी क्षेत्र में 923 और लुधियाना पश्चिमी क्षेत्र में 679 राशन डिपो संचालित किए जा रहे हैं। इन डिपुओं के माध्यम से लाभार्थियों तक गेहूं और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है।

विभाग का कहना है कि बाकी बचे लाभार्थी परिवारों को भी जल्द योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशासन ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने नजदीकी राशन डिपो से अनाज प्राप्त करें और किसी भी समस्या की स्थिति में विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें।

निजातम नगर फैक्ट्री में लगी आग मजदूरों ने भागकर बचाई जान

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

शहर के निजातम नगर स्थित वाई ए ट्रेडर्स फैक्ट्री में बुधवार तड़के अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर सो रहा था, जिसने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में काम करने वाले हरमीत सिंह रोजाना की तरह मंगलवार रात फैक्ट्री के अंदर ही सोए हुए थे। बुधवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे उन्हें बाहर से धुआं निकलने और आग की गर्मी का एहसास हुआ। जब वह कमरे से बाहर आए तो देखा कि फैक्ट्री के अंदर आग तेजी से फैल रही थी। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और फैक्ट्री मालिक राहुल तथा दमकल विभाग को घटना की सूचना दी।

सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दो दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कर्मचारियों ने करीब एक घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।

फैक्ट्री मालिक राहुल ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

होशियारपुर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, होशियारपुर। जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार पोल्ट्री फार्म, राइस शैलर, भट्ठों, छोटे उद्योगों और घरों में काम करने वाले नौकरों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। मालिकों को नौकरों के नाम, पते, फोटो और फिंगरप्रिंट सहित जानकारी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा किराए पर दिए गए मकानों और दुकानों में रहने वाले लोगों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। जिले में आम, नीम, पीपल और बरगद के हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थिति में वन विभाग की अनुमति जरूरी होगी। प्रशासन ने मिलिट्री रंग की गाड़ियों और वर्दी के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। वहीं नहरों, चौ डैम और ब्यास नदी किनारे बने धुस्सी डैम में जानवरों को नहलाने और पानी पिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 7 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे।

एक अंक से चूका करोड़ों का लॉटरी इनाम

भारतेन्दु संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का। जिले में एक लॉटरी टिकट खरीददार उस समय सदमे में आ गया, जब वह महज एक अंक के अंतर से एक करोड़ रुपये का इनाम जीतने से चूक गया। फाजिल्का के मेहरियां बाजार निवासी पवन कुमार ने नागालैंड स्टेट लॉटरी का टिकट खरीदा था।पवन कुमार ने बताया कि उनके टिकट का नंबर 61बी 49531 था, जबकि एक करोड़ रुपये का इनाम 41बी 49531 नंबर पर निकला। सुबह जब वह लॉटरी विक्रेता के पास टिकट मिलाने पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। एक अंक से बड़ा इनाम चूकने की खबर सुनते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और बीपी अचानक कम हो गया।लॉटरी विक्रेता बोबी ने तुरंत उन्हें नींबू पानी पिलाया और एसी में बैठाकर राहत दी। कुछ समय बाद उनकी हालत में सुधार हुआ।

सीवेज पानी से परेशान हुए ग्रामीणों का सड़क पर प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, रोपड़

गांव कोटला निहंग के लोगों ने सड़क पर जमा सीवेज के गंदे पानी की समस्या को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से सीवरेज पाइपों की सफाई नहीं होने के कारण नालियां और पाइप जाम हो गए हैं, जिसके चलते सीवरेज का पानी सड़क पर बह रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क रोपड़ से करीब 50 गांवों को जोड़ती है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।

लोगों का कहना है कि सीवेज का पानी लगातार सड़क पर जमा रहने से सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई लोग गड्ढों और फिसलन के कारण गिरकर घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों को हाथ-पैर में चोटें भी आई हैं।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि प्रशासन जल्द से जल्द सीवरेज व्यवस्था को ठीक करे और सड़क से गंदा पानी हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या की जानकारी स्थानीय स्तर पर भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाकर लोगों को राहत देने की मांग की है।

पीएनजी सुविधा वाले परिवारों को तीन माह में कनेक्शन लेने के निर्देश, एलपीजी आपूर्ति पर असर

अमृतसर में पीएनजी कनेक्शन को लेकर सख्ती

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर

पीएनजी अपनाने से ऊर्जा बचत और सुविधा बढ़ेगी

जिला प्रशासन ने शहर और जिले के उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जहां अधिकृत एजेंसी की ओर से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है या घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने की सुविधा मौजूद है। प्रशासन ने ऐसे सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पीएनजी कनेक्शन अवश्य प्राप्त कर लें।

जिला प्रशासन की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और संबंधित राजपत्र अधिसूचना के आधार पर जारी की गई है। इसके अनुसार, जिन क्षेत्रों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले सभी पात्र परिवारों को नोटिस जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर अधिकृत एजेंसी से घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा और कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) पल्लवी शर्मा, आईएएस ने बताया कि निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे परिवारों को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लागू नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद की जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

उन्होंने कहा कि एलपीजी से पीएनजी की ओर बदलाव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल ईंधन उपलब्ध करवाना है। पाइप्ड नेचुरल गैस के इस्तेमाल से ईंधन आपूर्ति को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रशासन ने नागरिकों से इस पहल में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि पीएनजी कनेक्शन लेने से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए लोग अपने क्षेत्र के अधिकृत पीएनजी सेवा प्रदाता अथवा जिला प्रशासन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीति को आगे बढ़ाने और सुरक्षित ईंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

सतलुज फिल्म विवाद में सुखबीर बादल का ऐलान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

ऑनलाइन प्रसारण मंच जी5 से दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। इस मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अकाली दल इस फिल्म को पंजाब के हर गांव और कोने तक पहुंचाएगा। सुखबीर बादल ने सामाजिक माध्यम पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह फिल्म पंजाब के एक दर्दनाक दौर और हजारों सिख युवाओं व हस्तियों से जुड़े अत्याचारों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से अवगत कराने के लिए इस फिल्म का प्रदर्शन जरूरी है।

बादल ने आरोप लगाया कि उस दौर की सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है और शिरोमणि अकाली दल ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने फिल्म को ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा बताते हुए इसे पंजाब के लोगों तक पहुंचाने का ऐलान किया।

रोडवेज हड़ताल से पंजाब में बस सेवाएं हुईं प्रभावित

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों को बुधवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों के विरोध के चलते राज्य के 19 डिपो प्रभावित हुए हैं, जिससे बड़ी संख्या में बस सेवाएं बाधित हो गईं।

पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रधान रेशम सिंह गिल ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का भरोसा दिया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी कारण उन्हें मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

हड़ताल के कारण पंजाब के कई हिस्सों में बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।

अग्निकांड दुगरी स्कूल में अचानक भड़की आग, समय रहते बच्चों को बचाया

स्कूल के जनरेटर रूम में लगी भीषण आग

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

महानगर के पॉश इलाके दुगरी में बुधवार सुबह एक नामी स्कूल में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दुगरी फेज-1 स्थित राम लाल भसीन पब्लिक स्कूल के जनरेटर रूम से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। घटना के समय स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं और बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। हालांकि स्कूल प्रबंधन की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्कूल परिसर में बने जनरेटर रूम में अचानक आग लग गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही जनरेटर रूम से काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में लपटें तेज हो गईं। इसे देखकर स्कूल स्टाफ और शिक्षकों में चिंता का माहौल बन गया।

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छुट्टी घोषित कर दी। स्कूल के सभी गेट खोल दिए गए और शिक्षकों व कर्मचारियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद बच्चों को स्कूल वाहनों और अभिभावकों की सहायता से सुरक्षित घर भेज दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जनरेटर रूम में लगी आग पर पानी की बौछारें शुरू कर दीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और उसे स्कूल की मुख्य इमारत व कक्षाओं तक पहुंचने से रोक दिया गया।

गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस और फायर सेफ्टी विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा स्कूल में सुरक्षा इंतजामों और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। स्कूल प्रबंधन ने भी भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की बात कही है।

आग की घटना के बाद स्कूल परिसर में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है। प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को बिजली उपकरणों की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

डेयरी कारोबार सीखने का सुनहरा मौका

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

डेयरी व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं के लिए डेयरी विकास विभाग की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विभाग 13 जुलाई से फगवाड़ा स्थित डेयरी ट्रेनिंग सेंटर में दो सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण कोर्स शुरू करेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आधुनिक डेयरी संचालन की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे स्वरोजगार के रूप में डेयरी व्यवसाय को बेहतर तरीके से शुरू कर सकें।

डेयरी विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को दुधारू पशुओं की खरीद, पशु आहार प्रबंधन, नस्ल सुधार, पशुओं की देखभाल, डेयरी संचालन, दूध की गुणवत्ता बनाए रखने और बाजार में उचित विपणन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को जरूरी प्रशिक्षण सामग्री भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए विभागीय योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार 2.5 और 10 दुधारू पशुओं की खरीद पर सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 33 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस प्रशिक्षण में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार का कम से कम पांचवीं कक्षा पास होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए प्रशिक्षण शुल्क 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है।

जिला जालंधर के इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन डिप्टी डायरेक्टर डेयरी विकास कार्यालय, आर.डी.डी.एल. कॉम्प्लेक्स, लाडोवाली रोड पर 10 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर डेयरी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है।

प्लास्टिक प्रदूषण रोकना है तो पैकेजिंग व्यवस्था पर करनी होगी सख्ती

पर्यावरण संरक्षण आज के युग की सबसे बड़ी अनिवार्यताओं में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनमे से एक 'सिंगल-यूज प्लास्टिक' पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। यह एक सराहनीय कदम प्रतीत होता है, परंतु इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन के तरीके ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। क्या हम केवल छोटे दुकानदारों का चालान काटकर पर्यावरण को बचा सकते हैं, जबकि बड़ी कंपनियां और उत्पादन इकाइयां आज भी धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग कर रही हैं। इस पर गहनता से विचार करें तो निम्न बिंदु उभर कर सामने आते हैं

छोटे दुकानदार बनाम बड़ी कंपनियां वर्तमान व्यवस्था में एक बड़ी विडंबना यह है कि प्रशासन की सख्ती अक्सर रेहड़ी-पटरी वालों या छोटे किराना दुकानदारों तक ही सीमित रह जाती है। यदि एक सब्जी वाला प्लास्टिक की थैली देता पकड़ा जाए, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि वह थैली आई कहां से? जब तक उन फैक्ट्रियों पर ताले नहीं लगेंगे जहां यह प्लास्टिक बन रहा है, तब तक छोटे दुकानदार इसे कहीं न कहीं से प्राप्त करते रहेंगे। यह मांग और आपूर्ति का सरल नियम है। सरकार को अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन औद्योगिक इकाइयों पर केंद्रित करना चाहिए जो इन प्रतिबंधित सामग्रियों का निर्माण कर रही हैं।

हरिराम धीमान
नालागढ़, जिला सोलन

पैकेजिंग का मायाजाल : आज हम किसी भी बड़े मॉल या सुपरमार्केट में चले जाएं, वहां मिलने वाली 90त्न वस्तुएं प्लास्टिक में लिपटी होती हैं। खाद्य सामग्री: टॉफियां, चिप्स, बिस्कुट, ब्रेड, दूध और दही—ये सभी चीजें मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक में आती हैं। यह प्लास्टिक री-साइकिल करना सबसे कठिन होता है। नए कपड़े अक्सर एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग में आते हैं, जिस पर एक और प्लास्टिक का टैग लगा होता है। इसके अतिरिक्त अनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों से आने वाले पार्सल में प्लास्टिक की इतनी परतें होती हैं कि मुख्य वस्तु से ज्यादा वजन प्लास्टिक कचरे का हो जाता है।

इन बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई करने के बजाय, सारा ठीकरा आम जनता और छोटे व्यापारियों पर फोड़ दिया जाता है। कंपनियों को सस्टेनेबल पैकेजिंग (जैसे कागज, जूट या बायोडिग्रेडेबल सामग्री) अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना चाहिए।

मूक शिकार- बेसहारा पशु और पर्यावरण: सड़कों पर बिखरा प्लास्टिक केवल दृश्यों को खराब नहीं करता, बल्कि यह एक जानलेवा जाल है। शहरों की सड़कों पर घूमने वाली गाएं और अन्य पशु भोजन की तलाश में इन प्लास्टिक के पैकेटों को चबा जाते हैं। चूंकि प्लास्टिक पचता नहीं है, यह उनके पेट में जमा होकर एक सख्त गोला बन जाता है, जिससे तड़प-तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा, जब यह प्लास्टिक मिट्टी में दबता है, तो यह भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देता है। नालियों में फंसकर यह जल निकासी व्यवस्था को ठप कर देता है, जिससे मानसून के दौरान शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है।

ईपीआर की विफलता और वास्तविकता : सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम बनाया है, जिसके तहत कचरा उत्पन्न करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे उसे वापस इकट्ठा करें, लेकिन धरातल पर यह नियम कागजी औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। कंपनियां उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाती हैं और कचरे की सफाई का बोझ नगर निगमों और आम जनता पर छोड़ देती हैं।

समाधान की राह : इस समस्या को केवल जुर्माने से नहीं, बल्कि एक समग्र रणनीति से हल किया जा सकता है। सरकार को प्लास्टिक बैग और हानिकारक पैकेजिंग बनाने वाली फैक्ट्रियों को वैकल्पिक उद्योग में बदलने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए और अवैध इकाइयों को पूरी तरह बंद करना चाहिए। अब समय जुर्माने का नहीं, जवाबदेही और बदलाव का है।

प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान केवल सरकार या प्रशासन के प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें उद्योगों व्यापारियों स्थानीय निकायों और आम नागरिकों सभी की समान भागीदारी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति यदि कपड़े या जूट के थैले का नियमित उपयोग करे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से दूरी बनाए और प्लास्टिक कचरे को अलग करके पुनर्चक्रण के लिए उपलब्ध कराए तो इसके सकारात्मक परिणाम जल्द दिखाई दे सकते हैं। विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को भी जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करना चाहिए। उद्योगों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग अपनानी होगी तथा उत्पाद के साथ उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे के संग्रह और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभानी होगी। जब उत्पादन से लेकर उपभोग और निस्तारण तक प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी तभी प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सफलता की ओर बढ़ें

मैं नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं और सकारात्मक सोच कैसे विकसित कर सकता हूं? यदि आपके मन में बार-बार नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक सकारात्मक सोच विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि नकारात्मक विचार आना कोई असामान्य बात नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, समस्या विचारों के आने में नहीं, बल्कि उन्हें सत्य मान लेने और बार-बार उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करने में होती है। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित दृष्टि से देखना होता है।

नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने का पहला तरीका यह है अपने विचारों को पहचानना। जब भी मन में कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे 'मैं यह काम नहीं कर सकता' मुझसे नहीं होगा या 'मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है', तो तुरंत रुककर स्वयं से पूछिए- 'क्या यह वास्तव में सच है?' अक्सर हम बिना प्रमाण के ही सबसे बुरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। विशेषज्ञ इसे 'कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग' कहते हैं, अर्थात किसी परिस्थिति को नए और अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना।

आचार्य दीप चंद
आध्यात्मिक चिंतक

दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन रात को सोने से पहले तीन ऐसी बातों को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत धीरे-धीरे आपके मस्तिष्क को कमी और समस्याओं के बजाय अवसरों और उपलब्धियों पर ध्यान देना सिखाती है।

तीसरा उपाय है सकारात्मक लोगों और प्रेरणादायक सामग्री के साथ समय बिताना। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनकी सोच का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। यदि आप प्रेरक कहानियां, जीवन-परिवर्तनकारी अनुभव और सफलता के वास्तविक उदाहरण पढ़ते हैं, तो आपका दृष्टिकोण स्वत: बदलने लगता है। अक्सर कहा जाता है कि यदि आप चार सफल व्यक्तियों के बीच रहते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि पांचवे सफल व्यक्ति आप होंगे। यहीं पर प्रेरणादायक साहित्य और कहानियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप हिंदी में ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं जो जीवन के संघर्षों में आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश दें, तो मोटिवेशनल किताबें आपके लिए एक उपयोगी मंच हो सकता है। मोटिवेशनल या सक्सेसफुल लोगों की प्रेरक कहानियां यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से अपना जीवन बदल सकता है।

यदि आप स्वयं से कहते हैं, 'मैं असफल हूं', तो उसे बदलकर कहिए, 'मैं अभी सीख रहा हूं और आगे बेहतर कर सकता हूं।' आप खुद से बोलें 'ऑल इस वेल, ऑल इस वेल'। शोध बताते हैं कि विचारों की यह पुर्नव्याख्या तनाव और चिंता को कम करने में सहायक हो सकती है। पांचवां उपाय है अपने शरीर का ध्यान रखना। पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है, तो मन भी अधिक स्थिर और सकारात्मक रहता है। अंत में याद रखें कि सकारात्मक मानसिकता एक दिन में विकसित नहीं होती। यह छोटे-छोटे दैनिक अभ्यासों का परिणाम है।

हर दिन अपने विचारों को परखें, कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रेरक साहित्य पढ़ें और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें, अच्छे तथा सफल लोगों से मिलें उनसे बातें करें। आप अपने को काफी मोटिवेटेड पाएंगे। यदि आप नियमित रूप से प्रेरणादायक हिंदी कहानियां और जीवन-मूल्यों से जुड़ी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, तो शहर की कोई अच्छी लाइब्रेरी आपके लिए एक अच्छा स्रोत बन सकता है, जहां, सकारात्मक सोच और जीवन-प्रेरणा से भरपूर सामग्री उपलब्ध हो।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> **आंतरिक** सौंदर्य का आह्वान करना कठिन काम है। सौंदर्य की अपनी भाषा होती है, ऐसी भाषा जिसमें न शब्द होते हैं न आवाज।
>
> -राजश्री

संपादकीय

गृह युद्ध की ओर बढ़ता पाकिस्तान

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल के दिनों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए टकराव ने एक बार फिर इस क्षेत्र की जटिल परिस्थितियों को अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, बढ़ते करों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लंबे समय से असंतोष जताने वाले लोगों का आंदोलन जब हिंसक झड़पों और गोलीबारी तक पहुंच गया तो यह स्पष्ट हो गया कि समस्या केवल कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि शासन और जनता के बीच बढ़ती दूरी की भी है। किसी भी क्षेत्र में जब नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं तो यह प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी होती है कि नीतियों और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की प्रमुख मांगें जीवन से जुड़ी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित रही हैं। स्थानीय नागरिक लंबे समय से सस्ती बिजली, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत, रोजगार के अवसर और स्थानीय संसाधनों पर अधिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। इन मांगों को यदि समय रहते संवाद और सकारात्मक नीति के माध्यम से संबोधित किया जाता तो स्थिति शायद इतनी तनावपूर्ण नहीं बनती। लेकिन जब जनता को यह महसूस होने लगे कि उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है तब असंतोष धीरे धीरे व्यापक आंदोलन का रूप ले लेता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात से तय होती है कि वह विरोध और असहमति को किस प्रकार संभालती है।

पाकिस्तान इस समय केवल आर्थिक संकट का सामना नहीं कर रहा बल्कि राजनीतिक और संस्थागत चुनौतियों से भी जूझ रहा है। बढ़ती महंगाई, विदेशी कर्ज, मुद्रा संकट, निवेश में कमी और बेरोजगारी ने आम नागरिक का जीवन कठिन बना दिया है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच लगातार टकराव, सत्ता संघर्ष और शासन में अस्थिरता ने प्रशासनिक क्षमता को भी प्रभावित किया है। जब आर्थिक कठिनाइयों के साथ राजनीतिक अस्थिरता जुड़ जाती है तब जनता का असंतोष और तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से स्थानीय असंतोष की घटनाएं सामने आती रही हैं। अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों में विकास, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर समय समय पर विरोध दर्ज कराया जाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ता जनाक्रोश इस व्यापक चुनौती का एक और संकेत माना जा सकता है। जब किसी देश के अलग अलग क्षेत्रों में जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आंदोलन करने लगे तो यह शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चिंतन का विषय बन जाता है।

लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं बल्कि जनता की बात सुनना, संवाद स्थापित करना और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करना भी है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का एक स्वाभाविक अधिकार माना जाता है। यदि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन का दायित्व है कि वह न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित करे और साथ ही बातचीत के माध्यम से समाधान खोजे। स्थायी शांति केवल संवाद, विश्वास और न्यायपूर्ण प्रशासन से ही स्थापित की जा सकती है। पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास पुन: प्राप्त करने की है। केवल प्रशासनिक सख्ती या सुरक्षा उपाय लंबे समय तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं बन सकते। सरकारों की सफलता इस बात से मापी जाती है कि वे नागरिकों को बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं कितनी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराती हैं। यदि आम नागरिक स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगें तो शासन के प्रति विश्वास कमजोर होने लगता है और सामाजिक असंतोष बढ़ता जाता है।

भारत के लिए भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोसी क्षेत्र की अस्थिरता का प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति पर पड़ सकता है। सीमा पार होने वाली गतिविधियों, आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में भारत को लगातार सतर्क रहना आवश्यक है। साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तथ्यात्मक और जिम्मेदार तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों से जुड़े मुद्दों और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को उठाता रहा है। क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखना पूरे दक्षिण एशिया के हित में है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर निष्पक्ष दृष्टि बनाए रखे और जहां भी आवश्यक हो वहां संवाद तथा शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करे। किसी भी विवाद या आंदोलन का स्थायी समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत, विश्वास निर्माण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव है। नागरिकों की वैध समस्याओं को समय रहते संबोधित करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

इतिहास यह बताता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सेना या हथियारों से अधिक उसके नागरिकों के विश्वास, संस्थाओं की मजबूती और सुशासन में निहित होती है। जब सरकार जनता के साथ संवाद बनाए रखती है और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करती है तब सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। इसके विपरीत यदि असंतोष लगातार बढ़ता रहे और संवाद के अवसर कम होते जाएं तो परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं।

-शिवांश धाकड़

एक दाना बचाना केवल भोजन बचाना नहीं, बल्कि किसान के पसीने का सम्मान करना है

ऐसी विडंबना है कि कोई एक निवाले को तरस रहा है और कोई भोजन को फेंक रहा है। आत्मा सिहर जाती है। भूख का कोई धर्म नहीं होता। भूख सिर्फ भूख होती है। वह पेट में आग लगाती है, और उस आग को न सोना बुझा सकता है, न नाम, न पहचान। जिसने भूख झेली है वही जानता है कि एक सूखी रोटी भी उस वक्त अमृत लगती है। और हम, जिनकी थाली भरी है, स्वाद बदलने के लिए खाना छोड़ देते हैं। एक तरफ बच्चा कूड़े के ढेर में रोटी का टुकड़ा ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ शादी-भोज में सैकड़ों किलो खाना कचरे में चला जाता है।

नरेंद्र भारती
स्वतंत्र टिप्पणीकार

भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। यह जीवन की धुरी है, संस्कारों का प्रतीक है, प्रकृति और मनुष्य के बीच का वह बंधन है जो दोनों को जोड़ता है। जब हम थाली में बचा हुआ खाना फेंक देते हैं तो हमें लगता है कि हमने बस एक निवाला बर्बाद किया है। पर सच्चाई यह है कि उस एक निवाले के साथ हम किसान की मेहनत, मां की जागी हुई रातें, धरती का ऋण और किसी भूखे की प्रार्थना भी फेंक देते हैं। गांव के खेत में जाकर देखो। किसान सुबह अंधेरे से पहले उठकर खेत की ओर चल देता है। उसके हाथों में हल है, आंखों में उम्मीद है। वह धूप में झुलसता है, बारिश में भीगता है, सर्द रातों में खेत की रखवाली करता है। महीनों तक वह अपनी नींद, अपना आराम, अपना शरीर सब कुछ मिट्टी को समर्पित कर देता है। जब फसल तैयार होती है तो उसके चेहरे पर जो चमक आती है वह किसी धन से कम नहीं होती। वह अनाज मंडी में नहीं बेचता, वह अपना जीवन बेचता है।

वह अनाज जब तुम्हारी थाली तक पहुंचता है तो उसके पीछे केवल किसान का श्रम नहीं होता। मां घंटों रसोई में खड़ी रहती है। वह जानती है कि तुम्हें क्या पसंद है, कितना तीखा खाते हो, कितना नमक ठीक लगता है। वह अपने हिस्से का आराम छोड़कर तुम्हारे लिए रोटी सेंकती है। धरती अपनी छाती चीरकर बीज को अंकुरित करती है। पानी, हवा, सूरज सब मिलकर उस एक दाने को तैयार करते हैं।

जब तुम वह दाना फेंक देते हो तो तुम्हें लगता है कि यह छोटी बात है। पर सोचो, यदि हर घर में एक निवाला रोज फेंका जाए तो एक दिन में कितना अनाज नष्ट होगा। एक महीने में कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। शहरों के होटल, शादी-विवाह, भोज-भंडारे में तो यह बर्बादी और भी बड़ी हो जाती है। सजे हुए टेबल पर आधा खाया हुआ खाना कूड़ेदान की शोभा बढ़ाता है। लोग कहते हैं पैसा दिया है तो जो मर्जी करेंगे। पर पैसा अन्न नहीं बना सकता। पैसा किसान का पसीना नहीं खरीद सकता। पैसा मां की ममता का मोल नहीं चुका सकता। समाज का दूसरा चेहरा भी देखो जहां एक तरफ थाली में खाना बचता है, वहीं दूसरी तरफ लोग भूखे सोते हैं। जहां एक तरफ लोग स्वाद बदलने के लिए खाना छोड़ देते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग भूख मिटाने के लिए पानी पीकर सो जाते हैं। यह विरोधाभास ही सबसे बड़ी पीड़ा है। हम भूल जाते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता।

आज थाली भरी है तो बर्बादी आसान लगती है। पर जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। बीमारी आती है, रोजगार छिन जाता है, प्राकृतिक आपदा आती है। उस समय वही बचा हुआ दाना सबसे कीमती हो जाता है। बुजुर्ग कहते थे कि अन्न का अपमान मत करो, नहीं तो एक दिन दाने दाने को तरसोगे।

यह कोई डराने की बात नहीं है। यह अनुभव का निचो है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने अन्न का आदर किया वे समृद्ध हुए। जिन्होंने इसे तुच्छ समझा वे समय की मार में बिखर गए। भोजन का अपमान केवल अन्न का अपमान नहीं है। यह संस्कारों का क्षरण है। जब हम भोजन को व्यर्थ फेंकते हैं, तब केवल अन्न की नहीं, अपनी कृतज्ञता की भी उपेक्षा करते हैं। अन्न का हर दाना किसान की मेहनत, प्रकृति की कृपा और परिवार के स्नेह का प्रतीक होता है। इसलिए उसकी बर्बादी केवल संसाधनों की हानि नहीं, बल्कि संवेदनाओं का अपमान भी है। अन्न की कद्र करने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। जितनी भूख हो उतना ही भोजन परोसना, थाली में उतना ही लेना जितना खा सकें और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाना जैसी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बच्चों को भी बचपन से सिखाना होगा कि थाली में भोजन छोड़ना अच्छी आदत नहीं है। जब वे जानेंगे कि हर दाने के पीछे किसान का पसीना और धरती का योगदान है, तब वे स्वयं भोजन का सम्मान करना सीखेंगे। भोजन से पहले एक क्षण रुककर धन्यवाद देना भी कृतज्ञता का सुंदर भाव है। यह धन्यवाद ईश्वर, किसान, प्रकृति या मां-किसी के लिए भी हो सकता है। यही भावना मनुष्य को विनम्र, संवेदनशील और संतोषी बनाती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

प्रभावशाली नेतृत्व की पहचान

संगीता बिजलानी

संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 1960 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वह भारतीय फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल रही हैं। बचपन से ही ग्लैमर और फैशन की दुनिया में रुचि रखने वाली संगीता बिजलानी ने अपने आत्मविश्वास और खूबसूरती के दम पर मॉडलिंग क्षेत्र में पहचान बनाई।

वर्ष 1980 में उन्होंने प्रतिष्ठित मिस इंडिया का खिताब जीतकर देशभर में लोकप्रियता हासिल की। इस सफलता के बाद उनके लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खुले और उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। संगीता बिजलानी ने अपने फिल्मी करियर में कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय व आकर्षक व्यक्तित्व से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई।

कविता

धरा का विलाप

कनुप्रिया, नूरपुर
जिला कांगड़ा (हि.प्र)

बड़े चाव से विधाता ने धरती को सजाया,
वन-उपवन, जीव-जंतु, हर बीज को उगाया।
अपनी ही सृष्टि पर वो बहुत इतराया,
नील व्योम ने भी तब मंगल गीत गाया।
लालच का झरना जब मानव में फूटा,
दिल विधाता का सैकड़ों बार टूटा।
देवर्षि देखता रहा धरा का हाल,
कटते रहे वन, उजड़ते रहे साल-दर-साल।
धरा का बीज पनपते ही कटने लगा,
मिट्टी से लिपटा जीवन सिसकने लगा।
आ गई बेला प्रलय की, व्योम से गिरी चिंगारियां,
त्राहिमाम-त्राहिमाम पुकार उठीं दिशाएं सारी।
मौन भी उस दिन जैसे बोल उठा,
प्रकृति का हर कण डोल उठा।

फैशन केवल पहनावा नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की पहचान है

हर वर्ष 9 जुलाई को फैशन डे मनाया जाता है। यह दिन केवल नए कपड़े पहनने या बदलते फैशन रुझानों की चर्चा तक सीमित नहीं है बल्कि यह रचनात्मकता आत्मविश्वास और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भी उत्सव है। फैशन हमारे व्यक्तित्व का ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बिना कुछ कहे भी हम अपने विचार अपनी पसंद और अपनी पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यही कारण है कि आज फैशन जीवनशैली संस्कृति कला और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

ठाकुर हेमराज राणा
स्वतंत्र लेखक, सिरमौर

फैशन का अर्थ केवल महंगे कपड़े या प्रसिद्ध ब्रांड पहनना नहीं होता। सही मायनों में फैशन वह है जो व्यक्ति को सहज महसूस कराए और उसके व्यक्तित्व को निखारे। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है और यही विविधता फैशन की सबसे बड़ी खूबी है। किसी को पारंपरिक भारतीय परिधान पसंद होते हैं तो कोई आधुनिक परिधानों को अपनाता है। कोई सरल और सादगीपूर्ण पहनावे में विश्वास रखता है तो कोई रंगों और डिजाइनों के साथ नए प्रयोग करना पसंद करता है। यही स्वतंत्रता फैशन को विशेष बनाती है।

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में फैशन का स्वरूप अत्यंत समृद्ध और रंगों से भरपूर है। देश के अलग अलग राज्यों की अपनी पारंपरिक वेशभूषा है जो वहां की संस्कृति इतिहास और जीवन शैली को दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक टोपी और शॉल पंजाब का सलवार सूट राजस्थान का घाघरा चोली गुजरात की कढ़ाईदार पोशाक कश्मीर की फिरन तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी और उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं। समय के साथ इन पारंपरिक परिधानों को आधुनिक डिजाइनों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे वे नई पीढ़ी में भी लोकप्रिय हो रहे हैं।

फैशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मविश्वास है। जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद के कपड़े पहनता है और उनमें सहज महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास स्वत: बढ़ जाता है। अच्छे कपड़े केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि मानसिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि विभिन्न पेशों में अवसर और वातावरण के अनुसार पहनावे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालयों में वर्दी अनुशासन का प्रतीक होती है जबकि कार्यालयों में औपचारिक परिधान पेशेवर छवि को मजबूत बनाते हैं।

आज के समय में फैशन उद्योग विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में शामिल है। लाखों लोग डिजाइनिंग वस्त्र निर्माण कपड़ा उद्योग मॉडलिंग फोटोग्राफी विपणन ई कॉमर्स और फैशन पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय डिजाइनरों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विशेष पहचान बनाई है और भारतीय हस्तशिल्प तथा पारंपरिक कपड़ों को वैश्विक पहचान दिलाई है।

डिजिटल युग ने फैशन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां नए फैशन की जानकारी पत्रिकाओं और फैशन शो तक सीमित रहती थी वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के नए रुझान कुछ ही क्षणों में लोगों तक पहुंच जाते हैं। युवा वर्ग इंटरनेट और डिजिटल मंचों के जरिए नए डिजाइन रंगों और पहनावे के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अनेक छोटे डिजाइनर और स्थानीय कारीगर भी ऑनलाइन मंचों के माध्यम से अपने उत्पाद देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। इससे नए उद्यमियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिला है।

हालांकि फैशन की तेजी से बदलती दुनिया के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। अत्यधिक उपभोक्तावाद के कारण लोग जरूरत से अधिक कपड़े खरीदने लगे हैं जिससे संसाधनों का अनावश्यक उपयोग बढ़ता है। वस्त्र उद्योग में पानी ऊर्जा और रसायनों का व्यापक उपयोग पर्यावरण पर भी प्रभाव डालता है। इसी कारण आज टिकाऊ फैशन की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। टिकाऊ फैशन का उद्देश्य ऐसे कपड़ों का निर्माण और उपयोग करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हों लंबे समय तक उपयोग किए जा सकें और जिनके निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो।

पुनर्चक्रण जैविक कपास हस्तनिर्मित वस्त्र और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। फैशन का संबंध केवल कपड़ों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भी है। हमें ऐसे वस्त्र चुनने चाहिए जो स्थानीय कारीगरों के श्रम का सम्मान करें और पर्यावरण की रक्षा में सहायक हों। हाथ से बने कपड़े हथकरघा उत्पाद और पारंपरिक शिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं बल्कि लाखों कारीगरों की आजीविका का आधार भी हैं। यदि हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें तो इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।

फैशन के नाम पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। किसी की वेशभूषा उसके चरित्र क्षमता या व्यक्तित्व का अंतिम पैमाना नहीं हो सकती। वास्तविक सुंदरता व्यक्ति के व्यवहार विचार और आत्मविश्वास में होती है। फैशन तभी सार्थक है जब वह व्यक्तित्व को निखारे न कि दूसरों से तुलना या दिखावे का माध्यम बने। समाज में हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार सम्मानपूर्वक पहनावा चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

फैशन डे हमें यह संदेश देता है कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि सोच और आत्मविश्वास में भी होती है। यह दिन रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिकता का संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। बदलते समय के साथ फैशन भी बदलता रहेगा लेकिन उसकी मूल भावना हमेशा व्यक्ति की पहचान अभिव्यक्त करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की रहेगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

इटावा में हादसे का शिकार हुई बस चालक-परिचालक की मौत, यात्री घायल

एजेंसी, इटावा

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बनारस से दिल्ली जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े सरियों से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए।

घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार सुबह बनारस से दिल्ली जा रही निजी बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे खड़े सरियों से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में बस चालक और परिचालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

मृतकों की पहचान 35 वर्षीय प्रेम और 22 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है।

अधिकारियों के अनुसार घायल यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामान्य कराया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस हटाकर यातायात बहाल कराया।

योगी आदित्यनाथ बोले– आचार्य चाणक्य जैसे गुरु के ज्ञान से देश कभी विपन्नता की ओर नहीं बढ़ सकता

योगी सरकार का बड़ा कदम, डीबीटी से 1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों को मिले 1320 करोड़ रुपए

एजेंसी, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिक्षा को समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र में स्थायी विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों की पढ़ाई, विद्यालयों की स्वच्छता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाना शिक्षकों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। मुख्यमंत्री अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, बड़ा लालपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों तथा कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना का शुभारंभ किया। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में 1320 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के कैशलेस इलाज की सुविधा पर हर साल करीब 450 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका पूरा भार राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य की चिंता इसलिए कर रही है ताकि वे बिना किसी परेशानी के पूरी निष्ठा

और समर्पण के साथ नई पीढ़ी का भविष्य तैयार कर सकें।

मुख्यमंत्री ने आचार्य चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि देश को चाणक्य जैसा गुरु मिल जाए तो राष्ट्र कभी विपन्न नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में देश इतना मजबूत बनता है कि कोई भी विदेशी शक्ति आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई योजनाएं देश के लिए आदर्श बन रही हैं और विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शिक्षक देशभर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं लंबे समय तक चलती थीं, लेकिन अब शिक्षकों के सहयोग से परीक्षाएं केवल 15 दिनों में पूरी हो रही हैं और समय पर परिणाम घोषित किए जा रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने पिछले नौ वर्षों में परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और नकलमुक्त बनाया है। शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की गति को भी मजबूती मिली है।

न्यूज ब्रीफ

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य ने किया कान्हा गौशाला का निरीक्षण, की गौ सेवा

एजेंसी, बिजनौर। गौसेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य दीपक गोयल ने बुधवार को नुमाइश ग्राउंड स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंश को गुड़ खिलाकर पूजन और माल्यार्पण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में कुल 218 गौवंश संरक्षित मिले, जिनमें 24 नर और 194 मादा शामिल हैं। इस दौरान पांच गौवंश बीमार पाए गए। सदस्य ने पशु चिकित्सकों को बीमार पशुओं का समयबद्ध और बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता व्यवस्था और गौशाला की अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने को कहा। मौके पर पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

रील बनाने से मना करने पर नहर में कूदी किशोरी, दो दिन बाद मिला शव

एजेंसी, मीरजापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र में रील बनाने से मना किए जाने पर गंगा नहर में कूदी किशोरी का शव घटना के दो दिन बाद बुधवार को चंदौली जिले में बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार चंदौली निवासी खुशबू अपनी मां के साथ कौवासाथ गांव स्थित ननिहाल आई थी। छह जुलाई को मोबाइल से रील बनाने पर मां ने उसे डांट दिया था, जिसके बाद नाराज होकर उसने नारायनपुर पंप कैनाल से निकली गंगा नहर में छलांग लगा दी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। बुधवार को अलीनगर क्षेत्र में शव मिलने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सपा के पूर्व विधायक और करीबियों के लखनऊ सहित दूसरे ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

एजेंसी, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईडी की टीम ने लखनऊ के एल्डिको कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित अपार्टमेंट और झांसी जिले के कई परिसरों में जांच की। छापेमारी के दौरान आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। अधिकारियों ने कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, बैंक लेन-देन और चल-अचल संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों की जांच कर धन के स्रोत और मामले से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

जेपीएनआईसी बनाकर करोड़ों डकार गए अखिलेशः ओम प्रकाश राजभर

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि जेपीएनआईसी निर्माण में अनियमितताएं हुईं। राजभर ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने निर्माण लागत को लेकर भी सवाल उठाए और सपा नेतृत्व पर हमला बोला। हालांकि, उनके आरोपों पर सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

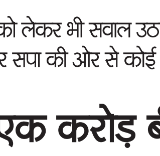

यूपी में शिक्षकों को मिलेगा, एक करोड़ बीमा और पांच लाख कैशलेस इलाज

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों और रसोइयों के लिए बड़ी सुरक्षा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को काशी से शिक्षकों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है, जहां शिक्षकों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया गया है। योजना के तहत स्थायी शिक्षक और कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा और 1.60 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा मिलेगा। वहीं, संविदा कर्मचारियों को 30 से 80 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।

सड़क खुदाई और अव्यवस्था पर विधायक का फूटा गुस्सा, अधिशासी अभियंता की लगाई क्लास

एजेंसी, उरई

उरई में अमृत योजना 2.0 के तहत शहर में चल रहे विकास कार्यों में लापरवाही की शिकायत मिलने पर बुधवार सुबह सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने मैकेनिक नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र में जगह-जगह खुदी सड़कों, अधूरे निर्माण कार्य और धीमी गति से चल रहे काम को देखकर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने भी विधायक को कार्यों में देरी और अव्यवस्था के कारण हो रही परेशानियों से अवगत कराया।

मौके पर ही विधायक ने जल निगम (शहरी) के अधिशासी अभियंता हिमांशु नेगी को फोन कर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए पहले ही निर्देश दिए गए थे कि अनावश्यक खुदाई से बचा जाए, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर सड़कें खोद दी गईं और उन्हें समय पर दुरुस्त नहीं किया गया। इससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक

गौरी शंकर वर्मा ने कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर तैनात कुछ मेट और कर्मचारी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं।

उन्होंने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और आवश्यकता पड़ने पर मामले को शासन स्तर तक उठाने की बात भी कही। निरीक्षण के दौरान मोहल्ले के लोगों ने मांग रखी कि जितनी सड़क खोदी जाए, उसे उसी समय भरने या अस्थायी रूप से दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। लोगों ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की भी मांग की। विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अमृत योजना 2.0 के सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने और कार्यों की प्रगति की निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदारों को भी समयसीमा का पालन करने तथा सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य करने को कहा गया।

'स्कूल चलो' अभियान के तहत चित्रकूट में निकली रैली, शिक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक

एजेंसी, चित्रकूट। सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के तहत चित्रकूट जिले में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को नगर पालिका परिसर से स्कूल चलो अभियान की जनपद स्तरीय जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से अभिभावकों और आम लोगों को बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया गया।

रैली का शुभारंभ जिला सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रंजना शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रंजना शुक्ला ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों का प्रवेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है और प्रत्येक बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला कराने की अपील की। जागरूकता रैली नगर पालिका परिसर से शुरू होकर पुरानी बाजार, धनुष चौराहा होते हुए वापस टंडन स्कूल के पास समाप्त हुई। इस दौरान बच्चों ने शिक्षा के महत्व से जुड़े संदेशों के साथ लोगों को जागरूक किया।

रैली में पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय कछारपुरवा सहित नगर क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सभासद शंकर प्रसाद यादव, खंड शिक्षा अधिकारी अतुल दत्त तिवारी, एसएस शुक्ला, प्रवीण दीक्षित, समन्वयक पुष्पेंद्र सिंह, हरिकांत, ज्ञानेंद्र मिश्रा, बीरेंद्र गुप्ता, कुलदीप सिंह सहित कई अधिकारी, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल चलो अभियान के माध्यम से अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना और उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है।

श्रावस्ती में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर एक की मौत, छह लोग गंभीर रूप से घायल

एजेंसी, श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह अन्य ग्रामीण घायल हो गए। पुलिस के अनुसार वाहन चालक कथित रूप से नशे की हालत में था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाहन को भी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 9:30 बजे गिरन्ट की ओर से आ रही स्कॉर्पियो (यूपी 46 एफ 0011) ने सबसे पहले बदला चौराहे पर इम्तियाज, सुभान अली, अरबाज और नबी अहमद को टक्कर मार दी। इसके बाद भी वाहन नहीं रुका और ग्राम पंचायत महरू पहुंचकर फिरोज तथा जहां महफूज उर्फ शेबू खान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल महफूज को तत्काल उपचार के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महफूज स्थानीय एचपी गैस एजेंसी के संचालक बताए जाते हैं।

◆ नशे में धुत चालक ने मचाया कहर, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

लगातार दो स्थानों पर हुई टक्कर के बाद ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो को रोक लिया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही बदला चौकी प्रभारी संदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और चालक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया। सभी घायलों को तत्काल निजी वाहनों से उपचार के लिए बहराइच भेजा गया। इसी दौरान एक और दुर्घटना सामने आई। मृतक महफूज के भाई राजा, हादसे की सूचना मिलने पर बहराइच जा रहे थे, तभी ग्राम पंचायत चिचड़ी के पास उनका भी सड़क हादसा हो गया, जिसमें वे घायल हो गए।

अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया टिप्पणी के विरोध में सपाइयों का प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

एजेंसी, प्रयागराज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही कथित आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियों के विरोध में बुधवार को प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को राममंदिर दान चोरी प्रकरण के आरोपी बताए जा रहे टुन्नू यादव से जोड़कर भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं। पार्टी का कहना है कि इस तरह की पोस्ट और संदेशों के माध्यम से अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह निराधार और

राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।

सपा नेताओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही ऐसी सामग्री न केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर रही है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने और तनाव का वातावरण बनाने का भी काम कर रही है। उनका कहना था कि इस प्रकार की टिप्पणियों से जनभावनाएं आहत हो रही हैं और गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।

साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रशासन ने ज्ञापन पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा सपा प्रतिनिधिमंडल को दिया।

सतनाम पंथ के साहेब जगजीवन दास की तपोस्थली कोटवा धाम का होगा विकास

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी जिले के सिरौलीगौसपुर तहसील स्थित कोटवा धाम के पर्यटन विकास के लिए 202.51 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। सतनाम पंथ के संस्थापक समर्थ साहेब बाबा जगजीवन दास की तपोस्थली पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत 150 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत 60.51 लाख रुपये की लागत से यात्री निवास, 13.07 लाख रुपये से शौचालय ब्लॉक और 36.13 लाख रुपये से वस्त्र परिवर्तन कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा भव्य प्रवेश द्वार, म्यूरल वॉल, सजावटी स्तंभ, पेयजल व्यवस्था, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, पेवर ब्लॉक, यात्री सुविधाओं का विस्तार

और अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे। करीब 356 वर्ष पुराने बाबा जगजीवन दास मंदिर और समाधि स्थल को सतनाम पंथ की प्रमुख तपोस्थली माना जाता है।

यहां प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर आयोजित जन्मोत्सव और मेले में प्रदेश सहित देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार सभी धर्मों और पंथों की आस्था का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है। कोटवा धाम के विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

स्वच्छता गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने की पहल, पर्यटकों से गंदगी नहीं फैलाने की अपील

वाराणसी में गंगा पार अभियान में हटाया गया 1000 किलो कचरा

एजेंसी, वाराणसी

सावन माह के आगमन और बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जीवनदायिनी गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को नगर निगम और नमामि गंगे के स्वयंसेवकों की संयुक्त टीम ने गंगा पार रेतीले क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान गंगा की रेत पर फैले करीब 1000 किलो कचरे को हटाया गया।

अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के समय गंगा का जलस्तर बढ़ने पर रेतीले क्षेत्र में पड़ा कचरा बहकर मुख्य जलधारा में पहुंच सकता था, जिससे नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर समय रहते गंदगी को हटाया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान टीम ने गंगा पार रेती पर फैले कपड़े, पॉलीथिन, प्लास्टिक की बोतलें, डायपर, पूजन सामग्री और अन्य

निर्माल्य को एकत्र किया। बड़ी मात्रा में एकत्रित किए गए कचरे को नगर निगम की विशेष नावों के माध्यम से किनारे तक लाया गया और फिर निस्तारण के लिए भेजा गया।

अभियान के दौरान गंगा किनारे मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी जागरूक किया गया। लोगों से अपील की गई कि वे गंगा घाटों और आसपास के क्षेत्रों में कचरा न फैलाएं और नदी को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इस दौरान 'सबका साथ हो, गंगा साफ हो' जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के उस पार स्थित रेतीले क्षेत्र में भी अब बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

उन्होंने कहा कि जिस गंगा किनारे लोग शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, वहीं कई बार अनजाने में गंदगी छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से गंगा लोगों की आस्था और जीवन का आधार रही है। इसलिए इसे प्रदूषण से बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बाढ़ आने से पहले गंगा पार फैले कचरे को हटाना बेहद जरूरी था, ताकि यह गंदगी नदी में न मिल सके।

स्वच्छता अभियान में नगर निगम और नमामि गंगे से जुड़े कई कर्मचारियों व स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अभियान में पुष्पलता वर्मा, शिवम रावत, देवेंद्र कुमार, शिवम कश्यप, अरुण कुमार, कामेश्वर सेठ, रिंकू सेठ, दिनेश चौधरी, सुनील कुमार, गोपाल, महेंद्र साहनी, हेमवती, रेखा, मंजू और लखी देवी सहित कई लोग शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि गंगा संरक्षण के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अभियान के दौरान लोगों ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने नियमित सफाई व्यवस्था जारी रखने की बात कही। और गंगा संरक्षण के लिए जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

ईवी सब्सिडी योजना से यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी रफ्तार

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण एवं मोबिलिटी प्रोत्साहन नीति-2022 का असर अब प्रदेशभर में दिखाई देने लगा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ईवी क्रय सब्सिडी योजना के तहत लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे अधिक आवेदन राजधानी लखनऊ से प्राप्त हुए हैं।

परिवहन विभाग के मुताबिक लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ में सबसे ज्यादा 12,520 आवेदन आए हैं। इसके बाद आगरा में 10,752, गौतमबुद्ध नगर में 6,088, गाजियाबाद में 5,556 और वाराणसी में 4,059 आवेदन दर्ज किए गए हैं। कानपुर नगर, सहारनपुर, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए योजना का लाभ लिया है। सरकार की इस योजना के तहत वाहन खरीदारों को आर्थिक राहत दी जा रही है। दोपहिया

◆ योगी सरकार की ईवी योजना, पांच हजार से 20 लाख तक सब्सिडी

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 5 हजार रुपये की सब्सिडी के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इससे खरीदारों को काफी बचत हो रही है।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि योजना के तहत गैर सरकारी ई-बसों पर 20 लाख रुपये तक, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक लाख रुपये तक और दोपहिया वाहनों पर 5 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक योजना का लाभ उठाने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में किफायती होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक हैं। इनके बढ़ते उपयोग से प्रदूषण कम होगा और कच्चे तेल के आयात पर खर्च में भी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

हांसी जल विवाद में 26 गांव जुड़े 168 दिन आंदोलन की तैयारी

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब आसपास के गांवों का भी व्यापक समर्थन मिलने जा रहा है। आंदोलन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से धरना कमेटी ने अगले 168 दिनों की विस्तृत रणनीति तैयार की है। इसके तहत रोघी और बूरा खाप से जुड़े 26 गांव आंदोलन में सहयोग करेंगे। हालांकि आंदोलन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार चानौत धरना कमेटी के पास ही रहेगा।

धरने के 53वें दिन बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण धरनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान आयोजित बैठक में आंदोलन को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धरना कमेटी के सदस्य अनूप चानौत ने बताया कि 26 गांवों में से प्रतिदिन एक गांव के 20 से 30 ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देंगे। इससे धरना लगातार सक्रिय बना रहेगा और ग्रामीणों की भागीदारी भी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार को एक गांव अपनी 36 बिरादरी के साथ चानौत पहुंचेगा और आंदोलन में भाग लेगा। इसी क्रम में अगले 26 रविवारों का कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया गया है।

इस योजना के माध्यम से लगभग छह महीने तक आंदोलन को निरंतर गति देने का प्रयास किया जाएगा। धरना कमेटी का कहना है कि पानी की समस्या का स्थायी समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सकारात्मक पहल करने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।

चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गंजा कर सड़कों पर घुमाया

गुस्से में वारदात करने की बात कही आरोपी ने, पुलिस जुटी हत्या के कारणों की जांच में

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

भाभी के भाई की चाकुओं से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी को गंजा कर सड़कों पर घुमाते हुए दिखाया गया है। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई और आरोपी के साथ किए गए व्यवहार को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पर आरोप है कि उसने गुस्से में आकर अपनी भाभी के भाई पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि गुस्से में उससे यह वारदात हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

इसी दौरान आरोपी का सिर मुंडवाकर उसे सड़क पर घुमाए जाने का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे अपराध के खिलाफ सख्त संदेश बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वायरल वीडियो को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच प्रक्रिया में सहयोग करें।

बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही पूरी घटना की तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं, वायरल वीडियो ने पुलिस कार्रवाई को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कुरुक्षेत्र में हत्या के आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई चर्चा में है। आरोपी पर भाभी के भाई की चाकू मारकर हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

रेवाड़ी में स्कूटी फिसलने से बी फार्मेसी छात्र की मौत

भारतेंदु संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में शहर के एक प्रमुख टेंट कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। हादसा झज्जर रोड फ्लाईओवर के पास हुआ, जहां युवक की स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। संतुलन बिगड़ने के बाद उसका सिर डिवाइडर के पास लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शहर के एक प्रतिष्ठित टेंट कारोबारी के बेटे के रूप में हुई है। वह गुरुग्राम में बी-फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह वह किसी कार्य से स्कूटी पर निकला था। झज्जर रोड फ्लाईओवर के निकट पहुंचते ही अचानक स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वाहन फिसल गया। गिरने के दौरान युवक का सिर सीधे बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को सड़क से उठाया और बिना समय गंवाए सिविल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल प्रशासन ने आवश्यक औपचारिकताओं के बाद घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। इस बीच हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें स्कूटी के फिसलने और युवक के गिरने की पूरी घटना कैद हुई है। पुलिस ने फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

न्यूज ब्रीफ

घरेलू विवाद में मासूम पर हमला, बच्ची को उठाकर सड़क पर पटका

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के रोहतक की संजय कॉलोनी में देर रात इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के दौरान एक युवक ने अपना गुस्सा सड़क पर खड़ी मासूम बच्ची पर उतार दिया। आरोपी ने पहले बच्ची को कई थप्पड़ मारे और फिर उसे हवा में उठाकर सड़क पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को पास खड़ी एक महिला ने तुरंत गोद में उठाकर निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। पूरी घटना पास लगे कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट करता दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। इसके बावजूद वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

गर्भवती टीजीटी शिक्षिका की नौकरी बहाल, हाईकोर्ट का निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण अवकाश मांगने वाली एक संविदा टीजीटी (साइंस) शिक्षिका की सेवा समाप्त करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि जब अन्य संविदा शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाई गईं, तब केवल मेडिकल आधार पर अवकाश मांगने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए संबंधित अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर शिक्षिका के पक्ष में नया नियुक्ति पत्र जारी करने और दो सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। यह आदेश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने महिला शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने 16 मार्च 2026 को जारी सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी है।

खजाने का झांसा देकर तंत्र-मंत्र के नाम पर डेढ़ करोड़ लेकर हुए फरार

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव जागधोली निवासी छमिंद्र सिंह से घर में दबे 19 क्विंटल सोने के कथित खजाने का लालच देकर तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ के नाम पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जोगिंदरनगर निवासी इरशाद, न्यू कॉलोनी बूड़िया निवासी मुन्नवर और अंबाला के धनौरा निवासी जंगशेर उर्फ जस्सी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने परिवार पर बुरे साये और जान-माल के नुकसान का भय दिखाकर अलग-अलग बहानों से लगातार रुपये वसूल किए। पीड़ित ने बताया कि वह मिट्टी के डंपर का काम करता है और गांव में शीतला माता मेले के दौरान आरोपियों से संपर्क हुआ था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर प्रेमजाल बिछाकर शिक्षक से लाखों की साइबर ठगी

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला। सोशल मीडिया पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती करने के बाद एक शिक्षक से 1.34 लाख 90 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। थाना साइबर क्राइम अंबाला ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता 52 वर्षीय करनैल सिंह, शिवालिक कॉलोनी, अंबाला शहर के निवासी हैं और महर्षि विद्या मंदिर स्कूल, जगाधरी में अध्यापक हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि 25 जून को फेसबुक पर मेरिट ज्यूक नाम की प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद आरोपियों ने विभिन्न बहानों से उनसे 1.34 लाख 90 हजार रुपये ठग लिए। पुलिस साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।

चारपाई और राशन पानी लेकर बिजली टावर पर चढ़े नौ किसान

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नौ किसान बुधवार को चारपाई, राशन और पानी के साथ एक बिजली टावर पर चढ़ गए। किसानों में एक दिव्यांग भी शामिल है। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने टावर के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया और किसानों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें कोई भी आत्मघाती कदम नहीं उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'कोई भी छलांग मत लगाना, मैं खुद मौके पर पहुंच रहा हूं।' इसके बाद प्रशासन और किसान नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों को शांतिपूर्वक नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गुरुग्राम पुलिस ने भारी बारिश के कारण कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की दी सलाह

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

लगातार हो रही बारिश और आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉरपोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और निचले इलाकों में जलभराव तथा यातायात जाम की स्थिति बनने की आशंका है।

ऐसे में अनावश्यक आवाजाही कम करना आवश्यक है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पुलिस द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि यदि कंपनियां अगले कुछ दिनों तक कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देती हैं तो सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी। इससे ट्रैफिक पुलिस को जाम की स्थिति से निपटने, जलभराव वाले क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन करने और एंबुलेंस, दमकल तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता साफ रखने में सहायता मिलेगी।

गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे बिना अत्यंत आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलें। यदि यात्रा करना जरूरी हो तो मौसम और यातायात की जानकारी लेकर ही निकलें तथा जलभराव वाले मार्गों से बचें।

वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गोदारा गैंग की धमकी पर हाईकोर्ट पहुंचे बलराज कुंडू, मांगी सुरक्षा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

रोहित गोदारा गैंग की ओर से लगातार मिल रही जान से मारने की कथित धमकियों के बाद महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ मौजूदा खतरे का नए सिरे से आकलन कराने की मांग की है। मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।

याचिका में बलराज कुंडू ने कहा है कि पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। हाल ही में विदेशी नंबरों से उनके व्हाट्सएप पर दो नए संदेश भेजे गए, जिनमें जान से मारने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि इन धमकियों के कारण उनके साथ-साथ परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पूर्व विधायक ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर खतरे के स्तर का दोबारा आकलन कराया जाए और उसके अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार, याचिका में संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। उधर, मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अदालत में याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल संबंधित एजेंसियां धमकी भरे संदेशों की जांच कर रही हैं।

सोनीपत में बारिश के बीच जर्जर मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर जेठानी-देवरानी की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत

जिले के गोहाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। जर्जर मकान की छत अचानक भरभराकर गिरने से कमरे में सो रही जेठानी और देवरानी मलबे में दब गईं। काफी प्रयास के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई।

मृतकों की पहचान 55 वर्षीय बिमला और 52 वर्षीय सुनील रानी के रूप में हुई है। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार दोनों महिलाएं मंगलवार रात भोजन करने के बाद पुराने मकान के एक कमरे में सोने चली गई थीं। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान पहले से ही कमजोर हो चुका था। देर रात अचानक कमरे की पूरी छत ढह गई और दोनों महिलाएं मलबे के नीचे दब गईं। हादसे के समय परिवार के अन्य सदस्य घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे, इसलिए उन्हें घटना की तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी। बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जब परिवार के सदस्य दोनों महिलाओं को जगाने पहुंचे तो कमरे की छत गिरी हुई देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कस्सी, फावड़े तथा अन्य साधनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में लगातार बारिश के कारण जर्जर मकान की छत गिरना हादसे की मुख्य वजह सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि गांव में इस दुखद घटना से मातम पसरा हुआ है।

हादसे के बाद प्रशासन ने क्षेत्र के पुराने और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण कच्चे और कमजोर मकानों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से गांव में जर्जर भवनों का सर्वे कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें खाली कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते ऐसे मकानों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जाएं तो भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जर्जर भवनों में रहने से बचें और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

आरटीआई मामले में तहसीलदार पर जुर्माना लापरवाही पड़ी भारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में चार वर्ष से अधिक की देरी को गंभीर लापरवाही मानते हुए गुरुग्राम के वजीराबाद के तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) सह-तहसीलदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम में निर्धारित 30 दिन की समय-सीमा का बिना किसी उचित कारण के उल्लंघन किया गया, जबकि अधिकारी की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने शिकायतकर्ता हरिंदर ढींगरा की शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। मामला आठ नवंबर 2022 को दायर आरटीआई आवेदन से संबंधित है। आयोग ने पाया कि निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इलाज का झांसा देकर महिला से कोरे कागजात पर लगवाया अंगूठा

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

शहर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ कथित तौर पर झूठी गवाही, वीडियो और दस्तावेज तैयार करवाने की साजिश के तहत 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को स्वास्थ्य जांच और अल्ट्रासाउंड कराने का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध पहले हरिद्वार और फिर दिल्ली ले जाया गया, जहां उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले जाकर उसे मानसिक रूप से डराया-धमकाया। इस दौरान उससे कथित रूप से झूठी गवाही दिलाने, वीडियो बनवाने और कुछ दस्तावेजों पर अंगूठा लगवाने का प्रयास किया गया। महिला को बाहरी लोगों से संपर्क करने का अवसर भी नहीं दिया गया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी तरह महिला आरोपियों के चंगुल से निकलकर रेवाड़ी पहुंची और अपने बेटे को पूरी घटना की जानकारी दी।

बेटे ने तत्काल पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूरी कार्रवाई एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई, ताकि निजी अस्पताल से जुड़े मामले में मनचाहे दस्तावेज और बयान हासिल किए जा सकें। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पीड़ित के बेटे की शिकायत पर नामजद महिला एजेंट शिल्पा और उसके सहयोगी रविन्द्र गुलिया के खिलाफ अपहरण, जबरन बंधक बनाने, डराने-धमकाने तथा अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

हरियाणा में बिछेगा ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जाल, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बड़ा आधार

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदेशभर में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, चार्जिंग सुविधाओं को सुलभ बनाना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहित करना है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को राज्य की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

हरियाणा के दोनों बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि परियोजना को गति देने के लिए विभिन्न जिलों में उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान का कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य एजेंसियों से खाली पड़ी और उपयोग योग्य जमीनों का विवरण मांगा गया है, ताकि वहां चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें। अधिकारियों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थानों पर विकसित किए जाएंगे, जहां आम लोगों की पहुंच आसान हो और इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, बस अड्डों, सरकारी परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई जा रही है।

सरकार का मानना है कि चार्जिंग ढांचे के विस्तार से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक चार्जिंग नेटवर्क का लाभ मिल सके।

हसनपुर के करीमपुर में तालाब में मिला तीन वर्षीय लापता मासूम का शव

मंगलवार से लापता था तीन वर्षीय प्रिंस, मंदिर में भंडारे के दौरान घर से निकला था मासूम, तलाश के बाद तालाब में मिला शव

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल

जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में मंगलवार से लापता चल रहे तीन वर्षीय बच्चे प्रिंस का शव बुधवार सुबह गांव के जोहड़ (तालाब) से बरामद हुआ। मासूम का शव मिलने की सूचना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

हसनपुर थाना प्रभारी हरीओम ने बताया कि करीमपुर गांव निवासी डिगपाल ने मंगलवार को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका तीन वर्षीय बेटा प्रिंस अचानक लापता हो गया है। शिकायत के अनुसार, परिवार के लोग गांव के राधा-रानी मंदिर में आयोजित भंडारे में शामिल होने गए थे। इसी दौरान प्रिंस घर से निकलकर पशुओं के प्लॉट की ओर चला गया था। जब परिवार के लोग भंडारे से वापस लौटे तो उन्हें प्रिंस घर पर नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने रिश्तेदारों और ग्रामीणों से भी जानकारी ली, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका।

काफी तलाश के बाद भी जब मासूम का सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए हसनपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस और ग्रामीणों की ओर से आसपास के इलाकों में बच्चे की खोजने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच बुधवार सुबह गांव के कुछ ग्रामीणों ने जोहड़ में एक बच्चे का शव देखा। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद हसनपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद

से शव को जोहड़ से बाहर निकलवाया। जांच के दौरान शव की पहचान लापता तीन वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई।

इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्चा खेलते समय जोहड़ में गिर गया होगा, लेकिन घटना के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

मासूम की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने भी इस घटना पर दुख जताया और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीमपुर गांव में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास मौजूद जलभराव वाले क्षेत्रों और तालाबों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में मंगलवार से लापता चल रहे तीन वर्षीय बच्चे प्रिंस का शव बुधवार सुबह गांव के जोहड़ (तालाब) से बरामद हुआ। मासूम का शव मिलने की सूचना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया।

अमित शाह ने 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी

दिल्ली परिवहन बेड़े में नई बसें शामिल, नरेला में अत्याधुनिक सुरक्षा जेल और आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत

एजेंसी ,नई दिल्ली

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की गई 300 नई प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई बसों के शामिल होने से दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई बसों में 195 नौ मीटर लंबी और 105 बारह मीटर लंबी आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। ये बसें कम ऊंचाई वाली और वातानुकूलित हैं। इनमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरे, आपातकालीन बटन, वास्तविक समय पर बस की स्थिति बताने वाली व्यवस्था और यात्री सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इस अवसर पर अमित शाह ने नरेला में बनने वाली अत्याधुनिक उच्च सुरक्षा जेल की आधारशिला भी रखी। इस जेल में 250 से अधिक कैदियों को रखने की क्षमता होगी। इसे देश की सबसे आधुनिक और तकनीक आधारित उच्च सुरक्षा जेलों में शामिल करने की योजना है। इस परियोजना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 100 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि शेष खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

नई जेल को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी कैमरे, शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे, जैविक पहचान प्रणाली, स्वचालित ताला व्यवस्था, पूरे शरीर की जांच करने वाली मशीनें, सामान जांच प्रणाली, मोबाइल संकेत रोकने वाली व्यवस्था, वीडियो माध्यम से सुनवाई, जेल परिसर में न्यायालय और अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी। जेल के डिजाइन को इस तरह तैयार किया जाएगा कि एक केंद्रीय नियंत्रण केंद्र से सभी हिस्सों की निगरानी की जा सके। प्रत्येक कैदी के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होगी, जिससे आपसी संपर्क, अपराधी समूहों के गठन और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम किया जा सकेगा। हर कक्ष में अलग शौचालय और स्नान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने बताया कि धुआं रहित इन बसों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या लगभग 6600 हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक लगभग 14 हजार बसों का आधुनिक बेड़ा तैयार करना है।

तीन साल बाद दिल्ली बाल अधिकार आयोग को मिला नया नेतृत्व

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने लगभग तीन वर्षों से खाली पड़े दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से आयोग में नए अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आयोग में अध्यक्ष पद पर व्यास को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राहुल गौतम, कुंदन कंसकर, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सभी नियुक्तियां उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।

बयान में कहा गया है कि करीब तीन साल से आयोग के पद खाली थे, जिसके बाद अब नए सिरे से इसका गठन किया गया है। ये नियुक्तियां बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2008 और केंद्रीय गृह मंत्रालय की संबंधित अधिसूचनाओं के तहत की गई हैं।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को मिलेगा नया बल

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके हितों को बढ़ावा देना और बच्चों से जुड़े मामलों की निगरानी करना है। आयोग बच्चों के शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। सरकार के अनुसार, अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। हालांकि, निर्धारित आयु सीमा पूरी होने पर कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

न्यूज ब्रीफ

भारी बारिश पर अमित शाह ने हालात की समीक्षा

एजेंसी ,नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और केरल के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर भारी बारिश से उत्पन्न हालात की जानकारी ली। उन्होंने राज्यों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने संबंधित राज्यों में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ जैसी परिस्थितियों और प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आवश्यकता पड़ने पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी राज्य सरकारों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और राहत एवं बचाव कार्यों में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि केंद्र सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है।

ई20 पेट्रोल पर केजरीवाल ने कंपनियों से मांगा जवाब

एजेंसी ,नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल के मुद्दे पर देश की 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पत्र लिखकर एक सप्ताह के भीतर लिखित जवाब मांगा है। उन्होंने कंपनियों से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वर्ष 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों में ई20 पेट्रोल का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि मारुति, टोयोटा और हीरो को अलग से पत्र भेजा गया है, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने हाल ही में दावा किया था कि ई20 के इस्तेमाल से केवल 3 से 5 प्रतिशत माइलेज कम होती है और वाहन को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कंपनियों के ओनर मैन्युअल में पुराने मॉडलों के लिए ई10 से अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कंपनियों से यह भी पूछा है कि यदि ई20 के उपयोग से वाहन को नुकसान होता है या माइलेज में अधिक गिरावट आती है, तो क्या वे उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी। साथ ही, उन्होंने गुरुवार को पेट्रोल पंपों और सर्विस सेंटरों पर जाकर उपभोक्ताओं से भी बातचीत करने की बात कही।

संगम विहार फैक्ट्री में भीषण आग, तीन घंटे बाद काबू

एजेंसी ,नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित होली चौक इलाके में बुधवार दोपहर एक प्लास्टिक डब्बे की पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई। आग से उठते धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिस फैक्ट्री में आग लगी वह कथित रूप से अवैध रूप से संचालित गत्ता और प्लास्टिक पैकिंग यूनिट थी। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, गत्ता और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा को घटना की सूचना दोपहर 11:52 बजे मिली। शुरुआत में कई दमकल गाड़ियां भेजी गईं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए लगातार अतिरिक्त वाहन बुलाए गए।

रामलीला तैयारियों पर डीडीए ने सहयोग का दिया भरोसा

एजेंसी ,नई दिल्ली । राजधानी में आगामी रामलीला समारोहों की तैयारियों को लेकर बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार ने दिल्ली धार्मिक महासंघ के पदाधिकारियों और विभिन्न प्रमुख रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में रामलीला आयोजनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने रामलीला स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं, साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए डीडीए से सहयोग का अनुरोध किया। इस पर डीडीए उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि राजधानी में रामलीला समारोहों के सुचारु, सुरक्षित और सफल आयोजन के लिए प्राधिकरण हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगा।

उपराज्यपाल संधू ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को दी मंजूरी

एजेंसी ,नई दिल्ली

राजधानी में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से उपराज्यपाल संधू ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की विभिन्न परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत सनोथ क्षेत्र में मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए 20 हेक्टेयर तथा नरेला में कास्टिंग यार्ड स्थापित करने के लिए 16 हेक्टेयर भूमि डीएमआरसी को आवंटित की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह भूमि आवंटन मेट्रो के विस्तार कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। सनोथ में बनने वाला मेट्रो डिपो ट्रेनों के रखरखाव, पार्किंग और परिचालन संबंधी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होगा। वहीं नरेला में प्रस्तावित कास्टिंग यार्ड में मेट्रो निर्माण के लिए आवश्यक प्रीकास्ट कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे परियोजना की गति बढ़ेगी और निर्माण कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा।

प्रशासन का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी, साथ ही सड़क यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।

भूमि आवंटन को राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डीएमआरसी अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाएगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि परियोजनाओं के तय समय पर पूरा होने से दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी। डीएमआरसी अधिकारियों ने बताया कि भूमि उपलब्ध होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी।

सरकारी स्कूलों की 12 बेटियों ने नवगुरुकुल में बनाई जगह, अब करेंगी कोडिंग की पढ़ाई

एजेंसी ,नई दिल्ली

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 12 मेधावी छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर नवगुरुकुल में प्रवेश प्राप्त कर नई उपलब्धि हासिल की है। इन छात्राओं का चयन आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास पर आधारित पाठ्यक्रमों के लिए किया गया है। अब ये छात्राएं कोडिंग के साथ साथ स्कूल ऑफ बिजनेस और बीसीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करेंगी।

इस उपलब्धि से न केवल छात्राओं के परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि उनके स्कूलों के शिक्षकों और साथियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी उचित मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के बल पर बड़े संस्थानों में अपनी जगह बना सकते हैं। नवगुरुकुल में चयनित छात्राओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल,

नेतृत्व क्षमता और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोडिंग की शिक्षा से उन्हें भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल उद्योगों में बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

वहीं स्कूल ऑफ बिजनेस और बीसीए जैसे पाठ्यक्रम उन्हें प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्र में मजबूत आधार देंगे। शिक्षकों का कहना है कि छात्राओं ने नियमित अध्ययन, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर यह सफलता अर्जित की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन छात्राओं की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और वे भी उच्च शिक्षा तथा आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में कोडिंग और डिजिटल शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारी स्कूलों की छात्राओं का इन पाठ्यक्रमों में चयन शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इससे यह संदेश भी जाता है कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय के सहयोग को दिया।

रोहिणी में ढहा निर्माणाधीन मकान

एजेंसी, नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बुधवार शाम रोहिणी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान अचानक ढह गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस तथा राहत एजेंसियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंच गए तथा राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के अनुसार, यह हादसा शाम करीब 4:20 बजे रोहिणी सेक्टर-16 स्थित एक एमसीडी स्कूल के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निर्माणाधीन भवन अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे उसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। अधिकारी ने बताया कि अब तक दो लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि यह अभियान जारी है कि कहीं और कोई व्यक्ति मलबे में फंसा न हो।

कथित दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने जीटीबी अस्पताल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

एजेंसी ,नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल के बाहर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपये के दवा और स्वास्थ्य उपकरण घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले तीन दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जनता को कथित दवा घोटाले की जानकारी दे रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, मशीनों और अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं।

आप प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि करीब 100 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में भारी कमीशनखोरी हुई। इसके अलावा उन्होंने एक्स-रे मशीनों की खरीद और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चादरों समेत अन्य सामान की कीमतों में भी कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि लगभग 10 लाख रुपये की बाजार कीमत वाली एक एक्स-रे मशीन को करीब 33 लाख रुपये में खरीदा गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों और सामान की खरीद में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है, जिसकी जांच आवश्यक है।

उन्होंने इस मामले में राजीव रंगीला को कथित तौर पर जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि वह पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार है। भारद्वाज ने कहा कि जांच एजेंसियों को इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि कथित घोटाले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। आप नेताओं ने कहा कि जनता के पैसों का हिसाब सरकार को देना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में मानसून सक्रिय, नोएडा में झमाझम बारिश के बाद आईएमडी ने यलो अलर्ट जारी किया

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही दिल्ली के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में भी बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई स्थानों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़कों पर पानी जमा होने और बारिश के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में बारिश को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी क्षेत्र के कई

हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बारिश के कारण सुबह के समय कार्यालय और स्कूल जाने वाले लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दीं और यातायात की गति धीमी रही। हालांकि, बारिश ने गर्मी और प्रदूषण से परेशान लोगों को राहत भी दी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की सक्रियता के चलते दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है।

प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखने और जरूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से जहां मौसम सुहावना हुआ है, वहीं लोगों को जलभराव और यातायात जैसी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

दो स्कूटी को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार कार बच्चों पर चढ़ी,मचा हड़कंप

एजेंसी, ग्रेटर नोएडा । ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन्स-2 सोसाइटी के बाहर बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल बस का इंतजार कर रहे बच्चों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जबकि एक बच्ची कार के नीचे आ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, बच्चे रोज की तरह सोसाइटी के गेट के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक कार सवार महिला ने अचानक नियंत्रण खो दिया और वहां खड़े बच्चों को टक्कर मार दी। इससे पहले कार ने वहां खड़ी दो स्कूटियों को भी टक्कर मारी थी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के बाद सोसाइटी के लोगों में रोष फैल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय

यहां बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने कार चालक महिला के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना के बाद बच्चों के परिजनों में चिंता का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद पुलिस ने मौके से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।

महेश पई बनेंगे साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ

केनरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी महेश पई को मिली नई जिम्मेदारी, अक्टूबर से शुरू होगा कार्यकाल

एजेंसी, नईदिल्ली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने महेश मुरलीधर पई को साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और यह नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी। साउथ इंडियन बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में इस संबंध में जानकारी साझा की।

बैंक की ओर से बताया गया कि आरबीआई की मंजूरी के बाद महेश मुरलीधर पई की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव 16 जुलाई को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद बैंक के शेयरधारकों से भी मंजूरी ली जाएगी। आरबीआई की ओर से दी गई स्वीकृति के तहत यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। महेश मुरलीधर पई वर्तमान में केनरा

बैंक में प्रमुख महाप्रबंधक (डिजिटल बैंकिंग और नवाचार) के पद पर कार्यरत हैं। बैंकिंग क्षेत्र में उनके पास करीब तीन दशक का लंबा अनुभव है। अपने करियर के दौरान उन्होंने बैंकिंग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाई हैं।

इनमें रणनीतिक योजना, बैंक प्रशासन, कोष प्रबंधन, विदेशी मुद्रा कारोबार, खुदरा बैंकिंग, कृषि ऋण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वित्त जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को लेकर भी महेश पई का अनुभव महत्वपूर्ण माना जाता है।

केनरा बैंक में डिजिटल बैंकिंग और नवाचार से जुड़े कार्यों को संभालते हुए उन्होंने तकनीक आधारित बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में योगदान दिया है। उनके अनुभव को देखते हुए साउथ इंडियन बैंक को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बैंक नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेगा। साउथ इंडियन बैंक केरल स्थित एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जो देशभर में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बैंक लगातार डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

नए एमडी और सीईओ के रूप में महेश पई के सामने बैंक की विकास गति को बनाए रखने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी। महेश मुरलीधर पई की नियुक्ति को बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनके अनुभव और डिजिटल बैंकिंग की समझ से साउथ इंडियन बैंक को नई रणनीतियां बनाने में मदद मिलेगी। बैंक को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में ग्राहक सेवाओं के विस्तार और तकनीकी सुधारों को और गति मिलेगी। महेश पई के नेतृत्व में बैंक डिजिटल नवाचार, बेहतर ग्राहक सुविधाओं और मजबूत वित्तीय रणनीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।

शमी धाम मंदिर समेत सार्वजनिक स्थलों पर चला सफाई अभियान

एजेंसी ,नई दिल्ली

स्वच्छता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मेगा सैनिटेशन ड्राइव चलाया। इस अभियान के तहत निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया। अभियान की खास बात यह रही कि डिप्टी कमिश्नर ने खुद मौके पर पहुंचकर झाड़ू संभाली और सफाई कार्य में हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान धार्मिक स्थलों, बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। शमी धाम मंदिर परिसर में भी विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जहां आसपास के क्षेत्र से कूड़ा हटाया गया और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। मंदिर परिसर में साफ-सफाई के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने निगम के प्रयासों की सराहना की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्वच्छ शहर बनाने के लिए केवल निगम कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने में सहयोग करें।

मेगा सैनिटेशन ड्राइव के दौरान नालियों की सफाई, कचरे का निस्तारण और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित करना है। अधिकारियों ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। निगम ने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील की है।

जनसेवा में मिसाल बनी जेएंडके पुलिस तीर्थयात्रियों को सुरक्षित लौटाया खोया सामान

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी, तत्परता और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिचय दिया है। बनिहाल के लंगर ग्राउंड में खोया हुआ मोबाइल फोन और नकदी उनके असली मालिकों को सुरक्षित लौटाकर पुलिस ने न केवल श्रद्धालुओं का विश्वास जीता, बल्कि लोगों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा भी मजबूत किया। इन घटनाओं की तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने खुलकर सराहना की है। अधिकारियों के अनुसार, बनिहाल स्थित लंगर ग्राउंड में एक विवो कंपनी का मोबाइल फोन लावारिस अवस्था में मिला। पुलिस ने तुरंत उसे अपने कब्जे में लेकर उसके वास्तविक मालिक की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। आवश्यक जांच और पुष्टि के बाद मोबाइल फोन उसके असली मालिक को सुरक्षित सौंप दिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ईमानदारी की श्रद्धालुओं ने प्रशंसा करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान इस तरह की संवेदनशील और जिम्मेदार कार्यशैली यात्रियों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है। इसी दौरान एक अन्य घटना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान शुभम बुकारे को लंगर ग्राउंड में 8,900 रुपये नकद मिले। उन्होंने रकम को अपने पास रखने के बजाय तुरंत पुलिस हेल्प डेस्क पर जमा करा दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बिना देर किए पैसे के वास्तविक मालिक की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि यह राशि चंडीगढ़ निवासी राधिका की है, जिन्होंने अपने पैसे खोने की सूचना दी थी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने पूरी राशि उन्हें वापस सौंप दी। अपनी खोई हुई रकम वापस मिलने पर राधिका ने पुलिस और सीआईएसएफ के जवान का आभार व्यक्त करते हुए उनकी ईमानदारी और त्वरित सहायता की सराहना की। इन दोनों घटनाओं ने यह साबित किया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनात पुलिस और सुरक्षा बल केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता के लिए भी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। पुलिस और सीआईएसएफ के बीच बेहतर समन्वय के कारण यात्रियों की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

श्रीनगर में सीआईके का छापा, कई ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) शाखा ने बुधवार को श्रीनगर के कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों और जांच से जुड़े मामलों के संबंध में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

अनंतनाग में तीन आतंकी मददगार गिरफ्तार फेस रिकग्निशन सिस्टम से हुई पहचान

भारतेंदु संवाददाता, अनंतनाग। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लगाए गए फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) की मदद से अनंतनाग पुलिस ने आतंकियों के तीन ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सरबल क्षेत्र में सिस्टम से मिले अलर्ट के बाद तीनों संदिग्धों को रोककर उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में उनके आतंकी संगठनों से जुड़े होने की पुष्टि होने पर उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है।

कुपवाड़ा में रेवेन्यू रिकॉर्ड में धोखाधड़ी के लिए पूर्व पटवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

भारतेंदु संवाददाता, कुपवाड़ा। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने कुपवाड़ा ज़िले में पैतृक ज़मीन पर धोखाधड़ी से मालिकाना हक का दावा करने के लिए सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी और जालसाज़ी के कथित मामले में तत्कालीन पटवारी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है। यह पटवारी अभी नायब तहसीलदार के तौर पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धाराओं 167, 417, 466 और 468 के तहत दर्ज प्राथमिकी नंबर 33/2021 में कुपवाड़ा के सब-जज/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में बाबापोरा हैहामा, कुपवाड़ा के रहने वाले लियाकत अली खान के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। अपराध के समय वे पटवारी के तौर पर काम कर रहे थे और अभी नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने हलका हैहामा/गुंडी सना में स्थित संयुक्त मालिकाना हक वाली पैतृक ज़मीन को धोखाधड़ी के ज़रिए अपने और अपने भाई के नाम ट्रांसफर करने के लिए सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी।

पुंछ के मंडी इलाके में भालू के हमले लगातार जारी, एक महिला गंभीर रूप से घायल

भारतेंदु संवाददाता, अनंतनाग। जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले की मंडी तहसील के अराई मलकान इलाके में बुधवार को भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस इलाके में ऐसी घटनाओं का यह लगातार तीसरा दिन है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अराई मलकान की रहने वाली और मोहम्मद ताज की पत्नी तज़ीम अख्तर पर उस समय भालू ने हमला कर दिया जब वह अपने घर के पास रोज़मर्रा के काम में लगी हुई थीं। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुँचे तब तक भालू उन्हें गंभीर रूप से घायल करके भाग गया। घायल महिला को एम्बुलेंस से मंडी के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उन्हें शुरुआती इलाज दिया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में मंडी तहसील के सवजियन, लोरन और अब अराई में भालू के हमले की ऐसी ही घटनाएँ सामने आई हैं जिससे लोगों में डर का माहौल है।

जीएमसी में इलाज दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम मौके पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जी.एम.सी.) राजौरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की देर शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज की जान गई। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान का इंतजार है।

अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर व 1 एक्सकेवेटर मशीन जब्त

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। जिले में अवैध खनन के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 डंपर और 1 एक्सकेवेटर मशीन को जब्त किया है। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस के समग्र पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली कार्रवाई में पुलिस चौकी की घाटी की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कठुआ, डीएसपी मुख्यालय कठुआ तथा थाना प्रभारी कठुआ के मार्गदर्शन में गश्त के दौरान घाटी क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के निर्माण सामग्री ले जा रहे दो डंपर नंबर जेके21एच-5678 और जेके02बीवी-1821 को कब्जे में लिया।

ट्रांजिट कैंप मनिगम में लापरवाही के आरोप में चार शिक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। गांदरबल के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने ट्रांजिट कैंप मनिगम में लापरवाही के आरोप में चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नोडल अधिकारी, ट्रांजिट कैंप मनिगम, सहायक आयुक्त राजस्व गांदरबल से प्राप्त पत्र के आधार पर की गई है। निलंबित शिक्षकों की पहचान बिलाल अहमद शेख पुत्र मोहम्मद हुसैन शेख निवासी हरिपोरा कंगन, आबिद मोहिउद्दीन भट पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन भट निवासी मनिगम, पीर मुदासिर पुत्र अब्दुल राशिद शाह निवासी वुस्सान और गौहर राशिद कुल्लू पुत्र अब्दुल राशिद कुल्लू निवासी गुंड के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की व्यवस्थाओं से संबंधित मामले में आगे की जांच लंबित रहने तक निलंबन आदेश जारी किया गया है।

बारामुला में बदले सियासी समीकरण सफीना बेग ने थामा एनसी का हाथ

फारूक और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में सफीना बेग ने जॉइन की नेकां

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब बारामुला जिला विकास परिषद (डीडीसी) की पूर्व चेयरपर्सन सफीना बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से पार्टी का दामन थामा। उनके इस फैसले को कश्मीर की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।

मुलाकात के दौरान सौहार्दपूर्ण बातचीत करते प्रमुख नेता।

सफीना बेग लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रही हैं। वह पूर्व उपमुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के सह-संस्थापक मुजफ्फर हुसैन बेग की पत्नी हैं। राजनीतिक जीवन के दौरान वह पीडीपी के अलावा सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ी रहीं। अलग-अलग राजनीतिक दलों में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू की है।

साल 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में सफीना बेग ने बारामुला जिले की वागूरा-क्रीरी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन क्षेत्र में उनकी सक्रियता और जनसंपर्क लगातार बना रहा। इससे पहले वह बारामुला जिला विकास परिषद की चेयरपर्सन के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जम्मू-कश्मीर हज कमेटी की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, जिससे उन्हें प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ।

नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद पार्टी नेतृत्व ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि सफीना बेग के अनुभव और जनाधार से संगठन को विशेष मजबूती मिलेगी, खासकर उत्तर कश्मीर के बारामुला क्षेत्र में। कार्यकर्ताओं ने भी उनके पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई और इसे संगठन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सफीना बेग का एनसी में शामिल होना केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। बारामुला और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव माना जाता है और ऐसे में उनके पार्टी में आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगामी राजनीतिक गतिविधियों में लाभ मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

शाह ने सीएम उमर को दिया हर संभव सहयोग का भरोसा

जेएंडके को मिलेगी हर संभव सहायता: शाह

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और कई क्षेत्रों में आए फ्लैश फ्लड के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य प्रशासन के साथ खड़ी है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

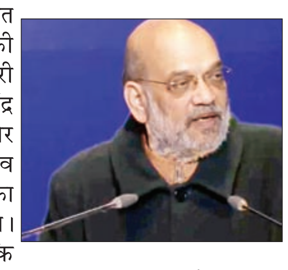

भारी वर्षा का सबसे अधिक असर चिनाब घाटी के जिलों में देखने को मिला है। डोडा जिले में अचानक आई बाढ़ और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग-244 प्रेमनगर के पास बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने मशीनों की मदद से मलबा हटाने और मार्ग को जल्द बहाल करने का अभियान शुरू कर दिया है।

मौसम की मार का असर वार्षिक मचैल यात्रा पर भी पड़ा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने तक यात्रा से बचें। दूसरी ओर किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट क्षमता वाली क्वार जलविद्युत परियोजना भी फ्लैश फ्लड से प्रभावित हुई है। तेज बहाव के कारण टेलरेस टनल क्षेत्र में पानी और मलबा भर गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और परियोजना के कुछ ढांचों को नुकसान पहुंचा है।

आसिम मुनीर के बयान के बाद सीमा पर अलर्ट, एलओसी पर बढ़ाई गई चौकसी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हालिया बयान के बाद जम्मू-कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस बयान को संभावित घुसपैठ और सीमा पार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के संकेत के रूप में देखते हुए पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। इसी के मद्देनजर सेना, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ तलाशी अभियान भी तेज कर दिए हैं।

◆ **सीमा पर अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां**

◆ **पाकिस्तान की संभावित घुसपैठ योजना पर नजर**

जानकारी के अनुसार रावलपिंडी स्थित जनरल मुख्यालय में आयोजित कोर कमांडर्स सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान इस विषय पर हर स्तर पर प्रयास करेगा।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते जनविरोध और आंतरिक चुनौतियों के बीच ऐसे बयान सीमा पर तनाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित गतिविधि को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा सकती है। इसे देखते हुए नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती मजबूत कर दी गई है।

9 से 12 जुलाई के बीच जम्मू में फिर सक्रिय होगा मानसून

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। मौसम विज्ञान केंद्र ने वीरवार को जम्मू और कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। जम्मू डिवीजन के कुछ स्थानों पर भारी बारिश, संक्षिप्त तीव्र बौछारें और गरज के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 जुलाई को जम्मू और कश्मीर के छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर संक्षिप्त तीव्र भारी बौछारें भी हो सकती हैं।

आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर संस्थान प्रमुख होंगे जिम्मेदार

जम्मू-कश्मीर के विश्वविद्यालयों में किताबों का जल्द होगा ऑडिट : एलजी सिन्हा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में आपत्तिजनक किताबें मिलने के बाद प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों का व्यापक ऑडिट कराने, किताबों की खरीद और जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने तथा संस्थान प्रमुखों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

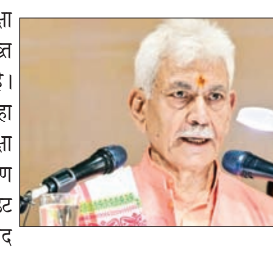

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में ऐसी सामग्री उपलब्ध न हो जो देश विरोधी, अलगाववादी या छात्रों को गुमराह करने वाली हो।

बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी नितीश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि अलगाववाद का महिमामंडन करने वाली किताबों की खरीद, स्वीकृति और वितरण से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है।

श्रीनगर के नौगाम में हादसा, वाहन की टक्कर से सीआरपीएफ के तीन जवान घायल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब जवान नियमित ड्यूटी के दौरान सड़क किनारे तैनात थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन ने संतुलन खो दिया और जवानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया तथा घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

◆ **तीन सीआरपीएफ जवानों को आई गंभीर चोटें**

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, तीनों जवानों को चोटें आई हैं, हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ पूरे घटनाक्रम की समीक्षा भी की।

पुलिस ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वाहन चालक की लापरवाही, तेज रफ्तार या अचानक नियंत्रण बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ।

अमरनाथ यात्रा के लिए नई एडवाइजरी जारी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) ने बुधवार को अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए एक नई सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें सभी यात्रियों से सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। सलाह के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी।

अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से जम्मू और कश्मीर की यात्रा से पहले अपना अग्रिम पंजीकरण पूरा करने और अपने पंजीकरण परमिट में उल्लेखित तिथि पर ही तीर्थयात्रा करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तत्काल पंजीकरण सीमित संख्या में उपलब्ध है और उपलब्धता के अधीन है। बिना पुष्ट पंजीकरण वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग की ओर बढ़ने के बजाय अपनी आवंटित यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है।

शोपियां में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनई ढेर, शव बरामद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों को आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर जाकिर अहमद गनी को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के मीमंदर क्षेत्र में चलाए जा रहे संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान की गई। अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।

एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, लश्कर का कमांडर मारा गया।

◆ **लश्कर के टॉप कमांडर को किया निष्क्रिय**

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मीमंदर क्षेत्र में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तीन जुलाई को तलाशी अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान कई दिनों तक लगातार जारी रहा। इसी दौरान सुरक्षाबलों का सामना आतंकियों से हुआ और हुई मुठभेड़ में जाकिर अहमद गनी मारा गया। पुलिस ने बताया कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय और शीर्ष कमांडर था तथा दक्षिण कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में उसकी भूमिका की जांच की जा रही थी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि संयुक्त अभियान के दौरान एक लश्कर आतंकी को मार गिराया गया है।

आस्था | अमरनाथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1.13 लाख श्रद्धालु पहुंचे गुफा

1.13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा, उत्साह और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक 1.13 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में स्थित बाबा बर्फानी के हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं और कठिन पर्वतीय मार्ग तय कर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

उपराज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।

श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यात्रा की मौजूदा स्थिति, सुरक्षा प्रबंध, तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं पूरी सतर्कता तथा संवेदनशीलता के साथ संचालित की जाएं।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक श्रद्धालु का पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जाए और यात्रा मार्ग पर तैनात अधिकारी तथा कर्मचारी यात्रियों की हर संभव सहायता करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल यात्रा का संचालन करना नहीं बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबा बर्फानी के दर्शन पूरी सुरक्षा और बिना किसी परेशानी के कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश की आस्था, एकता और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाती है तथा विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक शक्ति और समृद्ध परंपराओं को भी प्रदर्शित करती है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए यात्रा को सुरक्षित, सफल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का आह्वान किया।

समीक्षा बैठक में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इनमें मुख्य सचिव अटल डुल्लू, बिजली विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्वनी कुमार, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव तथा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनदीप के भंडारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कुलगाम में ट्रैफिक थमने से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मची अफरा-तफरी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में स्थित नवयुग टनल के पास बुधवार को यातायात बाधित होने से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों द्वारा जम्मू की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दिए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते नवयुग टनल से लेकर कुलगाम के मीर बाजार तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान निजी कारों, टैक्सियों, बसों, मालवाहक वाहनों और पर्यटकों से भरे वाहनों सहित सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक सड़क पर खड़ी रहीं।

अधिकारियों के अनुसार, यातायात रोकने के पीछे किसी विशेष घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, इस मार्ग पर अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा कारणों से समय-समय पर यातायात को नियंत्रित किया जाता है। प्राय: सुबह के समय पवित्र अमरनाथ यात्रा के काफिलों को सुरक्षित और निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराने के लिए जम्मू और श्रीनगर की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोकी जाती है। माना जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के तहत बुधवार को भी यातायात नियंत्रण किया गया, जिससे हाईवे पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया।

जाम के कारण सबसे अधिक परेशानी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे यात्रियों, पर्यटकों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हुई। कई लोग घंटों तक वाहनों में बैठे रहे। गर्म मौसम और लंबे इंतजार के कारण यात्रियों को पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

न्यूज ब्रीफ

दिव्यांगजनों का चिकित्सा परीक्षण आज

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कल यानि 09 जुलाई (वीरवार) को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर आयोजन के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने जिला मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन किया है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस बोर्ड में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं अधिकारियों को नामित किया गया है, जिनमें ईएनटी विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा मेडिसिन विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह शिविर 09 जुलाई को प्रातः 10 बजे से अंतिम लाभार्थी के परीक्षण तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित लाभार्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि व समयानुसार शिविर में शामिल होने का आह्वान किया है।

सब-जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 11 को

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिला की दूसरी जिला स्तरीय सब-जूनियर लड़कों एवं लड़कियों की बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 11 जुलाई को भांबला स्थित बॉल बैडमिंटन ग्राउंड में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्लबों से करीब 100 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें केवल 2 जनवरी 2011 के बाद जन्मे खिलाड़ी ही पात्र होंगे। प्रतिभागियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, कौशल, फिटनेस और खेल तकनीक के आधार पर लड़कों और लड़कियों की टीमों के लिए 8-8 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर के बाद राज्य स्तरीय सब-जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में मंडी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए चयन, टूर्नामेंट, प्रेस और ग्राउंड समितियों का गठन भी किया गया है।

बालिका कबड्डी चयन परीक्षण 15-16 को

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला में कबड्डी विधा में बालिकाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षण 15 और 16 जुलाई 2026 को आयोजित किए जाएंगे। चयन परीक्षण अंडर-18 और 19 से 20 वर्ष आयु वर्ग में होंगे। अंडर-18 वर्ग में 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच जन्मी बालिकाएं तथा 19-20 वर्ष वर्ग में 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच जन्मी खिलाड़ी पात्र होंगी। चयन में 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग की प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य स्तरीय पदक विजेता तथा अंतरराष्ट्रीय, जूनियर/सब-जूनियर राष्ट्रीय, अंडर-18 यूथ नेशनल, एसजीएफआई (अंडर-17), खेलो इंडिया यूथ गेम्स और सीनियर नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेने या पदक जीतने वाली खिलाड़ी चयन के लिए पात्र होंगी। खिलाड़ियों की रिपोर्टिंग 15 जुलाई को सुबह 8 बजे होगी। प्रतिभागियों को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और चार पासपोर्ट आकार के फोटो साथ लाने होंगे। चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं, निःशुल्क आवास एवं भोजन सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए एनसीओई धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892-224807 पर संपर्क किया जा सकता है।

आईटीआई डिप्लोमाधारकों के साक्षात्कार कल

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। अणु की प्राइवेट कंपनी मैसर्स विमांशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर में सर्विस एंड इंस्टॉलेशन टैक्नीशियन के 8 पदों और अकाउंटेंट के एक पद को भरने के लिए 10 जुलाई को सुबह 10 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सर्विस एंड इंस्टॉलेशन टैक्नीशियन के पदों के लिए दसवीं, बारहवीं पास या किसी भी ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमाधारक 30 वर्ष या इससे अधिक आयु के फ्रेशर पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 15 हजार से 18 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। अकाउंटेंट के पद के लिए कंप्यूटर एवं अकाउंटेंसी का ज्ञान रखने वाले स्नातक पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा उसके पास अकाउंटेंस का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चयनित उम्मीदवार को 15 हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दें विद्यार्थी : राजेश धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने हटवाड़ स्कूल में विद्यार्थियों से किया संवाद

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी समान ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी केवल अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, नैतिक मूल्यों व सामाजिक जिम्मेदारी का विकास भी करें। आज के विद्यार्थी ही भविष्य के जिम्मेदार नागरिक, नेतृत्वकर्ता और राष्ट्र निर्माता हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा, तकनीक, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल और सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि इन माध्यमों का सही इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने और नई तकनीकों को सीखने में सहायक हो सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, विज्ञान प्रदर्शनी, वाद-विवाद और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां आत्मविश्वास, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए सुधार कर रही है। सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अपनाया गया है और विद्यार्थियों को बेहतर प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संवाद कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने करियर निर्माण, प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास से जुड़े प्रश्न पूछे। मंत्री ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मोदी सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाना कार्यकर्ताओं का दायित्व : अनुराग

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बड़सर में भाजपा जिला हमीरपुर के दो दिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का दायित्व है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। ठाकुर ने आवास, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से इन्हें जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण सत्रों में बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार और पन्ना प्रमुख व्यवस्था पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और सेवा भावना के साथ संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आईआईटी मंडी ने विकसित की भूस्खलन की पूर्व चेतावनी प्रणाली

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हर वर्ष जन-धन की भारी हानि होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने एक पूर्णतः परिचालनात्मक लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। इस परियोजना का नेतृत्व प्रो. डेरिक्स प्रेज़ शुक्ला ने अपने शोधार्थियों अंकित सिंह और नितेश धीमान के साथ किया।

यह प्रणाली स्थलाकृति की संवेदनशीलता तथा वास्तविक समय के वर्षा आंकड़ों के आधार पर भूस्खलन की संभावना का पूर्वानुमान लगाती है। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए समय रहते चेतावनी जारी होने से प्रशासन व आपदा प्रबंधन एजेंसियां आवश्यक एहतियाती कदम उठा सकती हैं। प्रो. शुक्ला के अनुसार, मानसून के दौरान यह वेब-आधारित प्रणाली प्रतिदिन भूस्खलन का पूर्वानुमान उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि उपग्रह आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियां आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रभावी माध्यम हैं, क्योंकि वे वैज्ञानिक आंकड़ों को समय पर उपयोगी निर्णयों में बदलने में सक्षम होती हैं। इससे विशेषकर मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय को मजबूती मिलेगी। इस प्रणाली के विकास के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डेटाबेस में दर्ज लगभग 26,000 भूस्खलन घटनाओं का विश्लेषण किया गया। एंसेंबल मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से विभिन्न भूस्खलन कारकों को एकीकृत कर संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया गया। साथ ही, पिछले 15 दिनों के वर्षा आंकड़ों के आधार पर गतिशील पूर्वानुमान देने वाला P-RIL मॉडल विकसित किया गया। अंततः स्थिर संवेदनशीलता मानचित्र और गतिशील मॉडल को संभाव्यता विश्लेषण के माध्यम से जोड़कर दैनिक जोखिम पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। आईआईटी मंडी ने इस प्रणाली के लिए एक वेब पोर्टल भी विकसित किया है, जहां उपयोगकर्ता वर्तमान दिन के साथ पिछले 3 दिनों के भूस्खलन पूर्वानुमान जोखिम श्रेणियों में देख सकते हैं।

ठगी के शिकार व्यक्ति को वापस मिले 8 लाख

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। जिला पुलिस ऊना के साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को 8 लाख रुपये वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। शिकायतकर्ता ने 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर ठगी गई राशि को होल्ड करवाया और पूरी रकम शिकायतकर्ता को वापस दिलाई। पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक साइबर सेल ऊना ने 155 मामलों में कुल 23 लाख 50 हजार 996 रुपये की ठगी राशि पीड़ितों को लौटाई है। पुलिस अधीक्षक ऊना ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। उन्होंने लोगों से ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करवाने का आग्रह किया है।

नूरपुर पुलिस ने 274 ग्राम चिट्टे सहित पंजाब के तीन आरोपी किए गिरफ्तार

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सीआईए की टीम ने पुलिस थाना डमटाल क्षेत्र में 274 ग्राम चिट्टा की बड़ी खेप पकड़कर अंतरराज्यीय नशा तस्करी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सीआईए स्टाफ, पुलिस जिला नूरपुर की टीम नियमित गश्त एवं मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान विश्वसनीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अमृतसर पंजाब से एक स्विफ्ट कार (पीबी06यू-7122) में सवार तीन व्यक्ति भारी मात्रा में चिट्टा/हेरोइन लेकर भदरोआ, कंडवाल एवं आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करने आ रहे हैं।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भदरोआ के समीप वन विभाग विश्राम गृह के पास नाकाबंदी की गई। संदिग्ध वाहन के पहुंचने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान पीछे की सीट पर बैठे आरोपी कुनाल अरोड़ा के कब्जे में मौजूद काले रंग के स्लिंग बैग से 274 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई, जिसे मौके पर विधिवत जब्त किया गया।

इसके साथ ही उक्त वाहन को भी कब्जे में लिया गया। इस संबंध में थाना डमटाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में कुनाल अरोड़ा (31 वर्ष) निवासी अमृतसर, पंजाब, हैरी (26 वर्ष) निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब तथा मोहित कुमार (37 वर्ष) निवासी अमृतसर, पंजाब शामिल हैं।

एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह मामला अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था तथा इसे किन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाना था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

रावी का बढ़ा जलस्तर बना खतरा

पठानकोट में 30 गांवों का संपर्क टूटने की आशंका, ग्रामीणों में डर का माहौल

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। मानसून के बीच रावी नदी और उससे जुड़े सुए उफान पर आने से पठानकोट के कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की कथित अनदेखी के चलते सरना, जमालपुर और फरीदानगर क्षेत्र के ग्रामीणों में डर का माहौल है। तेज बहाव के कारण फरीदानगर को जाने वाली मुख्य सड़क अंदर से कमजोर हो रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, सड़क किनारे बनी दुकानों और घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि सड़क या सुरक्षा दीवार बहती है तो करीब 30 गांवों का संपर्क टूट सकता है। स्थानीय दुकानदार जसवंत सिंह ने बताया कि पानी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और सड़क को नीचे से काटना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब दुकानदारों की आजीविका इसी रास्ते और दुकानों से जुड़ी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे समस्या लेकर विभागीय अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि पानी छोड़ना उनके नियंत्रण में नहीं है। स्थानीय निवासी सतपाल ने बताया कि पानी के तेज बहाव में ऐतिहासिक घराट (पनचक्कियां) बह चुके हैं। नहर में बहकर आए पेड़ भी पानी के प्रवाह में बाधा पैदा कर रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है।

फरीदानगर मार्ग को क्षेत्र की लाइफलाइन बताया जा रहा है। पिछले साल की बाढ़ के बाद बनाया गया अस्थायी डंगा भी अब कमजोर पड़ चुका है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नहरी विभाग के एसडीओ मोहित सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिल गई है। जेई को मौके पर भेजकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर जल्द नया डंगा बनाने का काम शुरू किया जाएगा।

वहीं, रणजीत सागर बांध की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। बांध का जलस्तर 508.51 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी स्तर और खतरे के निशान से काफी नीचे है। माधोपुर हेडवर्क्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसके 54 गेटों को संचालित करने के लिए मोटराइज्ड सिस्टम सहित कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं।

राष्ट्रीय मानकों पर परखे हिमाचल के 60 डोमेन स्किल ट्रेनर, बिलासपुर में प्रमाणन कार्यक्रम शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर के यूको आरसेटी परिसर में बुधवार को नेशनल एकेडमी ऑफ रुडसेटी, बेंगलुरु के असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन वर्टिकल के तत्वावधान में राज्य स्तरीय आठवें डोमेन स्किल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न आरसेटी संस्थानों से पहुंचे 60 डोमेन स्किल ट्रेनरों की तकनीकी दक्षता, व्यावसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण क्षमता का राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मूल्यांकन एवं प्रमाणन किया गया।

उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और दक्षता पर निर्भर करती है। प्रशिक्षक युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रमाणन कार्यक्रम प्रशिक्षकों के ज्ञान, तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण कौशल का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर उन्हें राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाणित प्रशिक्षक आगे प्रदेश के विभिन्न आरसेटी केंद्रों में युवाओं, महिलाओं और इच्छुक उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इससे नए उद्यमियों को तैयार करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश में आरसेटी संस्थानों की राज्य नियंत्रक डॉ. अंबिका साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य डोमेन स्किल ट्रेनरों की तकनीकी दक्षता का आकलन कर उन्हें प्रमाणित करना है। उन्होंने कहा कि आरसेटी संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न स्वरोजगार आधारित ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए प्रशिक्षकों का दक्ष और प्रमाणित होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि प्रमाणन कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन, कृषि उद्यमिता, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी, महिला टेलरिंग, कम्प्यूटरीकृत लेखांकन, कैंडल निर्माण, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी निर्माण सहित 20 विभिन्न ट्रेड शामिल हैं।

प्रतिभागियों ने बताया कि प्रत्येक डोमेन स्किल ट्रेनर वर्षभर में चार से पांच प्रशिक्षण बैच संचालित करता है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और इच्छुक उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण के बाद कई प्रशिक्षु अपना व्यवसाय शुरू कर स्वरोजगार अपना रहे हैं।

बिलासपुर कॉलेज में बंदरों के हमले से छात्रा घायल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी को बंदर या तो काट रहे है या बंदरों के डर से अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। इस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने के साथ उनमें डर की भावना भी बढ़ रही है। बुधवार को सुबह दस बजे महाविद्यालय के संगीत विभाग के पास एक छात्रा को बंदरों ने पीछे से आकर काट लिया। महाविद्यालय सुरक्षा कर्मी राकेश कुमार ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायल छात्रा को बंदरों से बचाया और महाविद्यालय प्राचार्य डॉ पीएस कटवाल को तुरंत सूचित किया। प्राचार्य महोदय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय के प्राध्यापक के सहयोग से छात्रा को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मानसी को बंदरों ने काट लिया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस विषय में जिला प्रशासन को भी सूचित किया गय गया है। आए दिन महाविद्यालय के कर्मचारी और विद्यार्थी बंदरों के आतंक का शिकार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही की जाए।

कार्यालय ग्राम पंचायत बाली चौकी
विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी (हि. प्र.)

निविदा सूचना

आज की बैठक में प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया गया है। कि ग्राम पंचायत बाली चौकी में वित्त वर्ष-2026-27 के लिए विभिन्न विकास कार्यो हेतु निष्पादन के लिए कुटेशन / निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। सभी निविदाएं दिनांक 14-07-2026 तक सायः 4:00 बजे तक कार्यालय ग्राम पंचायत बाली चौकी में पहुँच जानी चाहिए। सभी निविदाएं डाक द्वारा बन्द लिफाफे में प्राप्त की जाएगी। कोई भी निविदाएँ बाई हैंड नहीं ली जाएगी। इसके बाद निर्धारित दिनांक 15.07.2026 को पंचायत कार्यालय में बैठक कमेटी के सामने निविदाएं खोली जाएंगी।

क्रं.सं.	सामग्री का विवरण	प्रति इकाई
1.	रेत क्रशर	प्रतिफुट
2.	रेत दरिया	प्रतिफुट
3.	बजरी	प्रतिफुट
4.	ईंटे मिट्टी के भटठे की	प्रति ईंट
5.	शटरिंग	प्रति वर्गफुट
6.	वैल्डिंग/लोहा तथा सरिया	प्रति किलो
7.	सीमेंट ढलवान किराया लेवर सहित धामण से	पूरी पंचायत में
8.	जेसीबी/एलएनटी	प्रति घनमीटर/प्रति घंटा
9.	मनरेगा व सामान मद के साईन बोर्ड लिखवाई व पेंट सहित 2*3 व 3*4	प्रति बोर्ड
10.	केट वायर जो एग्रो से कम रेट पर होनी चाहिए	प्रति क्रेट
11.	सीजीआई शीट, फेंसिंग वायर, जीआई पाईप, पीवीसी पाईप, आरसीसी पाईप, पेंट इत्यादि	
12.	पत्थर किराया	प्रति टिप्पर/प्रति ट्रैक्टर

नियम व शर्तेंः- 1. निविदादाता के पास अपना पैन व जीएसटी नं होना चाहिए। 2. आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित एम फार्म होने अनिवार्य हैं। 3. कार्य सामग्री कार्य स्थल तक जहां तक गाडी जाती है उपलब्ध करवानी होगी। 4. निविदादाताओं को पास व रद्द करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास रहेगा। 5. शर्त पूरी न होने पर कुटेशन रद्द की जाएगी।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत बाली चौकी
विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी (हि. प्र.)

प्रगति — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में देश के 100 जिलों में बिलासपुर ने झटका 17वां स्थान

कृषि विकास में बिलासपुर जिले की नई पहचान

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी एवं परिणामोन्मुख क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की। बैठक में योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसानों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की नियमित मॉनिटरिंग एवं बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक माह की 4 तारीख को जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा से विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देशभर के 100 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश से बिलासपुर जिला भी शामिल है। यह जिले के लिए कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उपायुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा, फसल कटाई के बाद भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास, सिंचाई अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, किसानों को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण की बेहतर उपलब्धता तथा सुशासन एवं सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने जैसे छह प्रमुख उद्देश्यों पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इन सभी मानकों पर किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित देश के 100 जिलों में बिलासपुर ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर 17वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सभी विभागों के समन्वित प्रयासों को देते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार प्रतिबद्धता एवं टीम भावना के साथ कार्य किया जाता रहा तो आने वाले समय में बिलासपुर देश के अग्रणी जिलों में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

राहुल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करे तथा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध ढंग से कार्य करे। उन्होंने विभागों को समन्वित प्रयासों के साथ कार्य करते हुए किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय उपलब्धियों की नियमित समीक्षा, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति तथा बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया।

उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग साझा कार्ययोजना के तहत उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करें, ताकि जिले के किसानों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके और बिलासपुर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों में अपनी मजबूत पहचान बना सके। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ किसानों को जागरूक करने, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

क्रेच वर्कर व हेल्पर के पदों के लिए 28 तक आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर बिलासपुर सत्या ठाकुर ने बताया कि आंगनवाड़ी कम क्रेच केंद्र चंगर शहरी सर्कल में मानदेय आधार पर एक क्रेच वर्कर और एक क्रेच हेल्पर के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा लुहणू सर्कल सदर-1 में एक क्रेच हेल्पर पद के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाली महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच तथा संबंधित क्रेच केंद्र के फीडर क्षेत्र की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया 25 अंकों के आधार पर होगी, जिसमें शिक्षा, अनुभव, सामाजिक श्रेणी और साक्षात्कार शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे एसडीएम सदर कार्यालय बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा।

एलेक्सिया पुटेयास का खूबसूरत अंदाज

स्पेन। एलेक्सिया पुटेयास स्पेन की प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर हैं। उनका जन्म 4 फरवरी 1994 को हुआ था। वह अपनी शानदार तकनीक, नेतृत्व क्षमता और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने विश्व फुटबॉल में स्पेन का नाम रोशन किया है।

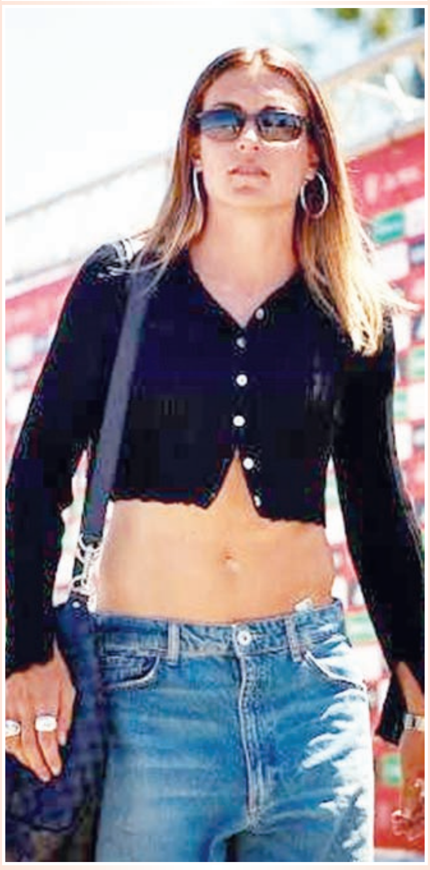

एंटीगा में दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा

वेस्टइंडीज ने 23 साल बाद श्रीलंका से जीती टेस्ट सीरीज

एजेंसी, एंटीगा

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। एंटीगा में खेला गया दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा, जिससे मेजबान टीम ने 23 वर्षों बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा किया। साथ ही फरवरी 2023 के बाद यह वेस्टइंडीज की पहली टेस्ट सीरीज जीत भी है।

पहले टेस्ट में पारी और बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद वेस्टइंडीज सीरीज में 1-0 से आगे था। दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने अंतिम दिन तेजी से रन बनाकर जीत की कोशिश की। कप्तान धनंजय डी सिल्वा, सोनल दिनुषा और मिलान रत्नायके ने तेज पारियां खेलीं, जिससे श्रीलंका ने दूसरी पारी 251/9 पर घोषित करते हुए वेस्टइंडीज के सामने 362 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि, अंतिम सत्र में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने बिना किसी नुकसान के 109 रन जोड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरे किए और इसके बाद दोनों टीमों ने ड्रॉ पर सहमति जताई।

इससे पहले श्रीलंका ने पहली पारी में 549/9 घोषित किए थे। लाहिरू उदारा ने 188 रन, सोनल दिनुषा ने 92 और कमिंदु मेंडिस ने 84 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने जस्टिन ग्रीव्स के 180 और शाई होप के 112 रन की बदौलत 499 रन बनाए। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने पहली पारी में पांच विकेट झटके।

गौतम गंभीर बोले-हमें खेल को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत

एजेंसी, नॉटिंघम

◆ **नई टीम को दें समय, हालात के मुताबिक खेलना होगा**

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में भारत की 76 रन पर शर्मनाक हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि टीम को खेल और परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। भारत लगातार चौथा टी-20 मुकाबला हार गया।

मैच के बाद गंभीर ने कहा, 'सिर्फ चार मैचों के आधार पर किसी टीम को खराब नहीं कहा जा सकता। कई बार विरोधी आपसे बेहतर खेलता है, लेकिन हमें हालात को पढ़ना और उसी के अनुसार खेलना सीखना होगा। आयरलैंड सीरीज के बाद से हम इसमें पीछे रहे हैं।' उन्होंने तेज गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजों की कमजोरी को स्वीकार किया, लेकिन इसे टीम की आक्रामक रणनीति का हिस्सा बताया। गंभीर ने कहा कि हम हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में कभी-कभी इस तरह के नतीजे भी सामने आते हैं। पिछले दो मैचों में हमने 190 रन बनाए थे, इसलिए इसे सिर्फ एक खराब दिन भी माना जा सकता है।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि पावरप्ले में पांच विकेट गंवाना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट रहा। उन्होंने कहा कि टीम को अपनी गलतियों से सीखकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। गंभीर ने टीम में हुए बड़े बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम की तुलना में मौजूदा टीम में कई नए खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी नहीं हैं, जबकि कुछ युवा खिलाड़ी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख रहे हैं। ऐसे में नई टीम को तैयार होने और अनुभव हासिल करने के लिए समय देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि टी-20 में छोटी-छोटी बातें, जैसे मैदान का आकार, हवा की दिशा और मैच की स्थिति को समझना, बड़ा अंतर पैदा करती हैं। खासकर मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाजों को जरूरत पड़ने पर पारी संभालने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

स्पोर्ट्स विंडो

सौरभ गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक जारी

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बहुप्रतीक्षित बायोपिक 'दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान हुआ। यह फिल्म 14 मई 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जारी पोस्टर में राजकुमार राव गांगुली के 2002 नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी लहराने वाले ऐतिहासिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। यह पल भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार और प्रतीकात्मक क्षणों में गिना जाता है। फर्स्ट लुक जारी होने पर गांगुली ने कहा कि जन्मदिन पर इससे बेहतर उपहार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पोस्टर ने उनके क्रिकेट करियर की यादगार यादों को फिर से जीवंत कर दिया। गांगुली ने राजकुमार राव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस किरदार को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया है। फिल्म में गांगुली के युवा क्रिकेटर से भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में शामिल होने तक के सफर, उनके संघर्ष, नेतृत्व और भारतीय क्रिकेट की सोच बदलने वाले फैसलों को दिखाया जाएगा। फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने ने किया है, जबकि निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है। इसे टी-सीरीज और डीबीएल प्रस्तुत कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के कैजुअल प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट में फिन एलन समेत चार खिलाड़ी शामिल

एजेंसी, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने 2026-27 सत्र के लिए फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साइफर्ट और एडम मिल्ने को कैजुअल प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है। चारों सीमित ओवरों के विशेषज्ञ हैं और अक्तूबर-नवंबर में भारत के खिलाफ होने वाली पांच टी-20 और पांच वनडे मैचों की घरेलू सीरीज के लिए चयन की दौड़ में बने रहेंगे। एनजेडसी ने स्पष्ट किया कि ये खिलाड़ी 2027 वनडे विश्व कप और उसके बाद होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारियों का भी हिस्सा रहेंगे। पिछले अनुबंध चक्र में कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाले पूर्व कप्तान केन विलियमसन अब सूची में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वहीं, जेम्स नीशम ने ऑकलैंड के साथ घरेलू अनुबंध किया है, जबकि डेवोन कॉनवे और ब्लेयर टिकनर की केंद्रीय अनुबंध सूची में वापसी हुई है। मुख्य चयनकर्ता गेविन लार्सन ने कहा कि चारों खिलाड़ियों ने कई मौकों पर ब्लैककैप्स के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन किए हैं। दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने से मिले अनुभव का फायदा न्यूजीलैंड टीम को भी मिलेगा। चारों खिलाड़ी फिलहाल मेजर लीग क्रिकेट 2026 में खेल रहे हैं। टिम साइफर्ट सिएटल ऑर्कास, फिन एलन सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, लॉकी फर्ग्यूसन वॉशिंगटन फ्रीडम और एडम मिल्ने टेक्सास सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जोकोविच ने खेला विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल

◆ **कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को 5 घंटे 15 मिनट में हराया**

एजेंसी, लंदन। 39 साल के नोवाक जोकोविच विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट पर अपने से 14 साल छोटे कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को 5 घंटे 15 मिनट में 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) से हराया। इससे पहले 2008 में रेनर शुटलर और अरनो क्लेमेंट के बीच का क्वार्टर फाइनल 5 घंटे 12 मिनट तक चला था। जोकोविच ओपन एरा में सबसे ज्यादा 5 सेट के ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम करियर का 50वां 5 सेट सिंगल्स मैच खेलकर स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका (49 बार) का रिकॉर्ड तोड़ा। वे ओपन एरा में किसी एक ग्रैंड स्लैम में 15 मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने। रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन और राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में यह उपलब्धि हासिल की है। सेंटर कोर्ट पर खेला गया मुकाबला शुरू से आखिर तक रोमांचक रहा। जोकोविच ने 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) से जीत दर्ज की। पांच घंटे से ज्यादा चले संघर्ष के बाद दोनों खिलाड़ी थक चुके थे और मुकाबले का फैसला पांचवें सेट के सुपर टाई-ब्रेक में हुआ।

फीफा विश्व कप: कोलंबिया को 4-3 से हराकर स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, वैंकूवर

फीफा विश्व कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने मंगलवार को रोमांचक मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अंतिम आठ में जगह बना ली। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त 30 मिनट का खेल गोलरहित बराबरी पर समाप्त होने के बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगोर कोबेल ने कुचो हर्नांडेज की पेनल्टी रोककर टीम की जीत की नींव रखी।

इससे पहले कोलंबिया के डेविंसन सांचेज की पेनल्टी क्रॉसबार से टकरा गई थी। स्विट्जरलैंड के मैनुएल अकांजी अपनी पेनल्टी चूक गए, लेकिन रुबेन वर्गास ने निर्णायक किक को गोल में बदलते हुए टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका सामना गत चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। वहीं, कोलंबिया का दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। इससे पहले उसने 2014 विश्व कप में अंतिम आठ में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार पेनल्टी शूटआउट में मिली हार के साथ उसका अभियान समाप्त हो गया।

फीफा विश्व कप: क्वार्टर फाइनल की आठों टीमें तय

एजेंसी, नई दिल्ली। फीफा विश्व कप अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। राउंड ऑफ-16 के सभी मुकाबले समाप्त होने के बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली आठों टीमों का फैसला हो गया है। अब खिताब की दौड़ में फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड बची हैं। इस विश्व कप में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। पराग्वे ने जर्मनी को हराकर इतिहास रच दिया, जबकि ब्राजील का 24 वर्षों बाद भी विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया और नॉर्वे ने उसे बाहर कर दिया। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराकर शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार विश्व कप खेलने वाली केप वर्डे ने भी अपने संघर्षपूर्ण खेल से प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

अर्जेंटीना की जीत पर भड़के मिस्त्र के कोच हुसाम हसन

एजेंसी, अटलांटा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में अर्जेंटीना से 3-2 की हार के बाद मिस्त्र के मुख्य कोच हुसाम हसन ने रेफरिंग और फीफा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टीम के साथ अन्याय हुआ और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को पक्षपातपूर्ण फैसलों का फायदा मिला।

हुसाम हसन ने मैच के बाद कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक के खिलाफ खेले और हर विभाग में उनसे बेहतर थे। लेकिन रेफरी पर एकतरफा दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से नतीजा हमारे खिलाफ गया। उन्होंने बताया कि मैच से पहले ही मिस्त्र ने रेफरी फ्रांसुआ लेटेक्सिए की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। हार के बाद उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम को एक स्पष्ट पेनल्टी नहीं मिली और दूसरा गोल भी गलत तरीके से रद्द कर दिया गया। हसन ने कहा कि हम इस जीत के हकदार थे, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। मैदान पर न तो फेयर प्ले दिखा और न ही सम्मान। फीफा 'फेयर प्ले' का नारा देता है, लेकिन मैदान पर उसका कोई असर नहीं दिखा। अगर रेफरी की गलतियां नहीं होतीं तो नतीजा अलग हो सकता था। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने रेफरी से भी तीखी बहस की। हसन ने बताया कि मैंने रेफरी से कहा कि यह बिल्कुल अनुचित है। शायद उनके मन में कोई बात थी जिसे वे छिपाना चाहते थे। जो लोग कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर सफल नहीं होते। अब मैं इस टूर्नामेंट का कोई और मैच नहीं देखूंगा। वहीं, मिस्त्र के कोच ने फीफा के मैच शेड्यूल पर भी सवाल उठाए।

अमेरिकी हमले के बाद ईरान बोला, हरगिज नहीं झुकेंगे

एजेंसी, मॉस्को

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालीबाफ ने बुधवार को कहा कि डराने-धमकाने और ब्लैकमेल करने से कोई नतीजा नहीं निकलता। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान हार नहीं मानेगा। बुधवार रात, अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई जबरदस्त हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई के जवाब में किए गए थे। इन हमलों को लेकर गालीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि धौंस जमाने और जबरन वसूली का दौर खत्म हो गया है। इससे कुछ हासिल नहीं होता। हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने अमेरिका पर उस समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के कई बार गंभीर उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया, जिस पर दोनों पक्षों ने 18 जून को हस्ताक्षर किए थे। इन उल्लंघनों में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने के लिए ईरान की तय व्यवस्था का उल्लंघन, नए हमलों की लगातार धमकियां, तेल पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करना, दक्षिणी ईरान पर हमले और लेबनान के खिलाफ इसराइल की लगातार आक्रामकता शामिल है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा दौरे पर

एजेंसी, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य में आयोजित होने वाले कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति भवन सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, मत्स्य क्षेत्र के विकास और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में सहभागिता करना है।

उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में गहरे समुद्री क्षेत्रों में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन के लिए प्राधिकरण-पत्र यानी एलओए जारी करने के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देश में गहरे समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों का वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ओडिशा गहरे समुद्र में मत्स्य पालन मिशन दस्तावेज का भी शुभारंभ करेंगे। यह मिशन समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके माध्यम से मछुआरा समुदाय को आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधन प्रबंधन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आयकर विभाग ने आईटीआर-5 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी किया

एजेंसी, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी सुविधा देते हुए आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-5 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। विभाग ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी। अब संबंधित करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से आईटीआर-5 की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर अपने रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं।

आईटीआर-5 फॉर्म का उपयोग विशेष श्रेणी के करदाताओं द्वारा किया जाता है। यह फॉर्म मुख्य रूप से कंपनियों के अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपीए व्यक्तियों के संघ और ऐसे समूहों के लिए होता है जो व्यक्तिगत करदाताओं की श्रेणी में नहीं आते। इसके माध्यम से ये संस्थाएं अपनी आय और कर संबंधी जानकारी आयकर विभाग को उपलब्ध कराती हैं।

इसके अलावा कॉर्पोरेट सोसायटी बिजनेस ट्रस्ट और निवेश फंड जैसी संस्थाएं भी आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-5 फॉर्म का इस्तेमाल करती हैं। यह फॉर्म इन संस्थाओं को अपनी वित्तीय जानकारी व्यवस्थित तरीके से विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की सुविधा देता है।

आयकर विभाग की ओर से जारी एक्सेल यूटिलिटी की मदद से करदाता ऑफलाइन तरीके से अपना रिटर्न तैयार कर सकते हैं।

चुनाव मध्यप्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी पर हाईकमान की नजर

चुनावी समर में उतरे पीके

एजेंसी, नई दिल्ली

चुनावी रणनीतिकार व जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरकर सबको चौंका दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हुए इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है. चर्चा है कि पीके ने सोची समझी रणनीति के तहत राजधानी पटना के सबसे पढे लिखे मतदाताओं के बीच उतरकर न सिर्फ भाजपाई रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए दूर का संदेश देने का प्रयास किया है।

यदि वे इस समर से विजयी होकर लौटते हैं तो इससे भाजपा को कड़ा झटका लगेगा और इसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण पर पड़ेगा. क्योकि इस समय जनसुराज यानी पीके की पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. इसलिए भाजपाई रणनीतिकार इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रहे हैं बल्कि एक विधानसभा के लिए नेताओं की बड़ी टीम उतारने को लेकर दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अंतर्कलह पर हाई कमान की नजर मध्यप्रदेश कांग्रेस में आरंभ हुआ शीतयुद्ध सुलझने के बजाय उलझने लगा है. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच मुद्दा विशेष को लेकर सामने आया मतांतर गुटबाजी का स्वरूप लेने लगा है।

हालांकि दोनों पक्षों की ओर से सबकुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है लेकिन अंदरखाने वरिष्ठ नेताओं बनाम युवा का अंतर्द्वंद्व धीरे धीरे सुलग रहा है. ऐसा नहीं है कि इस तरह की राजनीतिक हलचल से पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व बेखबर है. बल्कि पार्टी हाईकमान इस मुद्दे पर पैनी नजर लगाए हुए है. अभी तक संकेतों के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है लेकिन चर्चा है कि जल्द ही पार्टी रणनीतिकार किसी वरिष्ठतम नेता को भोपाल भेजकर इसे सुलझाने का प्रयास करेंगे।

नागपुर हवाई अड्डे पर बनेगा दूसरा रनवे, 10 गुना होगी यात्री क्षमता

एजेंसी, नई दिल्ली। नागपुर के बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अगले आठ साल में पूरी तरह कायाकल्प कर इसकी यात्री क्षमता बढ़ायी जायेगी तथा दूसरे रनवे और एक नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। हवाई अड्डे की परिचालक कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने बुधवार को एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अगले आठ साल के लिए एक महत्वाकांक्षी तीन चरण वाले विकास रोडमैप की घोषणा की।

साथ ही उसने बताया कि विस्तार योजना के तहत 30 साल में इसकी यात्री क्षमता मौजूदा 30 लाख सालाना से बढ़ाकर तीन करोड़ की जायेगी। उपलब्ध भूमि पर भविष्य में इसे बढ़ाकर पांच करोड़ तक करने की भी संभावना है। साथ ही इस हवाई अड्डे को एक प्रमुख कार्गो एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में भी विकसित करने की योजना है जिसकी दीर्घकालिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1.5 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। यह घोषणा नागपुर हवाई अड्डे के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत 30 साल के लिए जीएमआर को इसका संचालन सौंपा गया है। जीएमआर की इकाई जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) ने 25 जून 2026 को लगभग 1,000 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण पूरा कर हवाई अड्डे का परिचालन शुरू कर दिया था।

अरब सागर के ऊपर लापता हुआ पाकिस्तान का कार्गो विमान

एजेंसी, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से कराची आ रहा के2 एयरवेज का 27 साल पुराना बोइंग 737-400 कार्गो विमान रहस्यमय तरीके से अरब सागर में लापता हो गया है। विमान में 5 क्रू सदस्य सवार थे। स्थानीय समयानुसार सुबह 9:18 बजे विमान के नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी, जिसके मात्र तीन मिनट बाद ही यह रडार से तेजी से नीचे आते हुए गायब हो गया। यह विमान कराची से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह टूट गया।

विमान के गायब होने की सूचना मिलते ही पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने युद्ध स्तर पर खोज अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान नौसेना ने युद्धपोत पीएनएस जुल्फिकार और तुरबत के साथ-साथ एक एटीआर विमान को तैनात किया है, जबकि वायु सेना का साब निगरानी विमान भी अभियान में जुटा हुआ है।